सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

रिश्ते और पतंग जितनी उँचाई पर होते हैं, काटने वालो की संख्या उतनी अधिक होती हैं ।

वर्ष 01, अंक 237, नई दिल्ली

बुधवार, 08 नवम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

गुरुग्राम-फरीदाबाद में भी BS-3 और BS-4 वाहनों पर रोक, नियम तोड़ने पर 20 हजार का जुर्माना

पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग छाया हुआ है। एनसीआर के सभी जिले रेड जोन में हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद भी इससे अछूते नहीं हैं। मंगलवार को भी गुरुग्राम में एक्यूआई का स्तर 400 से ऊपर पहुंच गया।

गुरुग्राम/फरीदाबाद। लगातार प्रदूषित हो रही एनसीआर की हवा को देखते हुए दिल्ली से सटे हरियाणा के दोनों जिलों गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बीएस तीन (पेट्रोल) और बीएस चार (डीजल) श्रेणी के चार पहिया वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार देर शाम परिवहन आयुक्त के निर्देश पर दोनों ही जिलों के उपायुक्तों ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया। तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उपरोक्त आदेश 30 नवंबर या फिर ग्रैप की तीसरी स्टेज हटने तक लागू रहेगा। इस आदेश के बाद गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद के बीच जाने-आने वालों की परेशानी बढ़ेगी। दिल्ली में यह व्यवस्था पूर्व में ही लागू की जा चुकी है।

पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग छाया हुआ है। एनसीआर के सभी जिले रेड जोन में हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद भी इससे अछूते नहीं हैं। मंगलवार को भी गुरुग्राम में एक्यूआई का स्तर 400 से ऊपर पहुंच गया। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि लगातार बिगड़ रहे एक्यूआई के स्तर और लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही लोगों को सलाह दी जा रही है कि वह अब निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें।

सरकार गंभीर, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही हैं। प्रदेश में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अनेक कदम उठाए है। इसी क्रम में गुरुग्राम जिला में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जिले में

इन आदेशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिला वासियों को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला में अगर कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 194 (1) के तहत चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार नियम तोड़ने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

फरीदाबाद-गुरुग्राम के बीच कठिन हुआ सफर

नए आदेश के बाद सबसे ज्यादा परेशानी गुरुग्राम-फरीदाबाद के बीच सफर कठिन हो जाएगा। दोनों शहरों के बीच न तो सीधी मेट्रो सेवा है और न ही रेलवे की सुविधा है। मेट्रो और रेल का सफर करने वालों को दिल्ली तक का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा। इन दोनों ही शहरों के लोग बड़ी संख्या में काम के सिलसिले में प्रतिदिन आवागमन करते हैं। फरीदाबाद स्थित फैक्ट्रियों में जहां लोग गुरुग्राम से जाते हैं, वहीं एमएनसी और आईटी सेक्टर की कंपनियों में फरीदाबाद से लोग प्रतिदिन गुरुग्राम तक की दौड़ लगाते हैं। ज्यादातर चार पहिया वाहन वाले लोग इसके लिए ग्वाल पहाड़ी वाले रास्ते का प्रयोग करते हैं। इस रास्ते पर सफर करने वालों के लिए अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में सिर्फ रोडवेज बसों का ही सहारा है।

नगर निगम अधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर की कार्रवाई

शहर की हवा खतरनाक श्रेणी में जाने के बाद फरीदाबाद नगर निगम अधिकारियों ने सड़कों पर उतर कार्रवाई शुरु कर दी है। मंगलवार को निगम अधिकारियों ने अलग-अलग इलाकों में 76 चालाक काटे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1.67 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम मुख्य अभियंता बीरेंद्र कर्दम ने बताया कि पॉलीथिन का इस्तेमाल करने वाले 42 लोगों के चालान किए गए, 24 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार खुले में कूड़ा फैलने पर पांच लोगों पर सात हजार रुपये, कूड़े में आग लगाने वाले 21 लोगों पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना, तंदूर जलाने वाले पांच लोगों पर 25 हजार का, खुले में शौच पर 500 रुपये, खुले में मीट की दुकान का 500 रुपये, खुले में गाय छोड़ने पर पांच हजार रुपये के चालान किए गए है।

advertisement Tariff
w.ef. 1st January 2023

परिवहन विशेष

दिल्ली, एनसीआर से प्रसारित लोकप्रिय साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र

in Rs. / Sq. Cm.

	Basic	3rd Page	Back Page	Front Page Semi Solus	Front Page Solus
Delhi Aur Delhi	BW - Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Delhi	100*	200*	250*	300	300

Special Instructions:-

- Innovation on any page will be accepted at a premium of 100% on applicable card rate.
- Any specified position will be accepted at a premium of 25% on applicable card rate.
- B/W advertisement on page 3/Back will charged at colour rate.
- Classified display advertisement will be charged on basic display rate.
- Pointers 4x4 sq. C. or 5x4 sq. cm. will be charged as per card rate.
- box reply charges (each box) will be charged Rs. 150/-
- Political advertisement - as applicable.

परिवहन विशेष में विज्ञापन के लिए ऑनलाईन भुगतान सीधे बैंक खाते/फ़ोन पे पर कर सकते हैं और विज्ञापन के मैटर के साथ ऑनलाईन भुगतान की रसीद व्हाट्सऐप नंबर 09212122095 या newstransportvishesh@gmail.com पर भेज सकते है। भुगतान करने के लिए *NEFT / IMPS / RTGS*
Account Name:-Transport Vishesh Limited
IFSC CODE :- INDB0001396
Cur Account no :- 259212122095
या Phone pay :- 9212122095

दिल्ली सरकार ने ओड इवन के लिए 13 तारीख क्यों घोषित की, हिंदुओं का सवाल ?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। क्या दिल्ली सरकार या ओड इवन की तारीख की घोषणा करने वाले यह नहीं जानते या मानते की दीपावली का त्यौहार दीवाली पूजा पर नहीं भैया दूज मनाने के बाद पूर्ण होता है, फिर पहले ही हिंदुओं के प्रमुख पर्व दिवाली पर पटाखे जलाने पर रोक लगाने के बाद बाकी बचे पर्व पर भी आघात क्यों?

दिल्ली सरकार अपनी नाकामी को सिर्फ हिंदुओं के पर्व पर ही क्यों उतारती आ रही है? माननीय उच्चतम न्यायालय भी यह बात कह चुकी है की ओड इवन एक दिखावा है ओर सरकार प्रदुषण नियंत्रण कैसे करें इसका स्थाई हल बताए और उस पर अमल करके दिखाए।

सवाल हिंदुओ से जुड़ा है इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा, सीक्यूएमआई के चैयरमैन कुट्टी और दिल्ली के सबसे प्रमुख उपराज्यपाल जवाब अवश्य दे।

दिल्ली में 13 से चौथी बार ऑड-ईवन होगा लागू सुप्रीम कोर्ट ने कहा-अवैज्ञानिक, कुछ नहीं किया

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद 13 नवंबर से चौथी बार फिर से ऑड-ईवन को लागू किया जा रहा है। वहीं ऑड-ईवन को सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'अवैज्ञानिक' बताया। कहा कि आपने प्रदूषण कंट्रोल पर कुछ नहीं किया। लगातार दिल्ली में मानक स्तर के पार पहुंचे एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) ने परंपरागत दिल्ली सरकार को योजना पर अमल करने पर मजबूर होना पड रहा है। जिसमें सबसे पहले दिल्ली सरकार ने सभी प्राइमरी से लेकर 11वीं तक की स्कूल क्लास को फिलहाल 10 नवंबर तक बंद कर दिया है। अब सवाल लाजमी है कि इन अस्थाई बंदिशों से कितना फर्क पडेगा? लोगों ने साल- दर- साल ,हर-बार के स्कूल बंद पर यहां तक कह डाला कि सरकार को चाहिए कि वह 'पल्यूशन हॉलीडे' की रस्म अदायगी पर अमल करें। बहरहाल अब 13 से 20 नवंबर तक ऑड-इवन योजना को लागू किया जाएगा।

13,15,17,19 तारीखों को यानि 1,3,5,7,9 वाली गाडियां और 14,16,18,20, तारीखों को 0,2,4,6,8, वाली गाडियां ही चलेगी। योजना की अवधि बढाने का फैसला 20 नवंबर के बाद होगा। उल्लेखनीय है कि साल 2019-12 दिन, 2020-4 दिन, 2021-8 दिन, 2022-4 दिन, और अब 2023-7 दिन की मियाद रखी गई है।

इस बावत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और संबधित विभागो के अधिकारियों के साथ बैठक कर माथापच्ची की। बैठकों के दौर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी से पूछ लिया कि आखिर कब खत्म होगा प्रदूषण? सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया कि जिसमें कहा गया कि प्रदूषण के आंकलन के लिए देशभर में जिला स्तर पर स्थाई एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से नीतिगत है। क्या आप सोचते है कि एक्सपर्ट कमिटी बना देने से प्रदूषण खत्म हो जाएगा? बाद में याचिका वापस ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे बैन का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं था, बल्कि आदेश पूरे देश में पटाखों पर रोक लगाने का था। इसी क्रम में कोर्ट ने पंजाब समेत सभी जगह पर पराली जलाने से रोकने के आदेश दिए गए थे। हम नहीं जानते कैसे करना है ,यह काम आपका है। *कोर्ट ने कहा ऑड-इवन एक दिखावा है।

चालान नहीं भरने वाली कारों को एक दिसंबर से नहीं मिलेगा पीयूसी प्रमाणपत्र, इस राज्य का फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

इस राज्य सरकार ने फैसला किया है कि यदि वाहन मालिक ने लंबित चालान का भुगतान नहीं किया है, तो वाहनों को 1 दिसंबर, 2023 से प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

केरल में यदि वाहन मालिक ने लंबित चालान का भुगतान नहीं किया है, तो वाहनों को 1 दिसंबर, 2023 से प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला सोमवार को परिवहन मंत्री एंटनी राजू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

बैठक ने निष्कर्ष निकाला कि एआई कैमरे की स्थापना के बाद से पांच महीनों में यातायात दुर्घटनाओं से मृत्यु दर में गिरावट आई है।

यह भी पाया गया कि जून 2023 से 31 अक्तूबर 2023 के बीच राज्य में वाहन दुर्घटनाओं में 1,263 लोगों की मौत हुई, जो 2022 में इसी अवधि के दौरान हुई 1,669 मौतों से कम है।

सितंबर में, यातायात दुर्घटनाओं में 273 मौतें हुईं, जो पिछले वर्ष के इसी महीने में हुई 365 मौतों से कम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अक्तूबर 2022 में 340 यातायात दुर्घटना मौतें हुईं, लेकिन इस अक्तूबर में सिर्फ 85 मौतों के साथ उल्लेखनीय रूप से कम आंकड़ा दर्ज किया गया। यहां ध्यान देने वाली

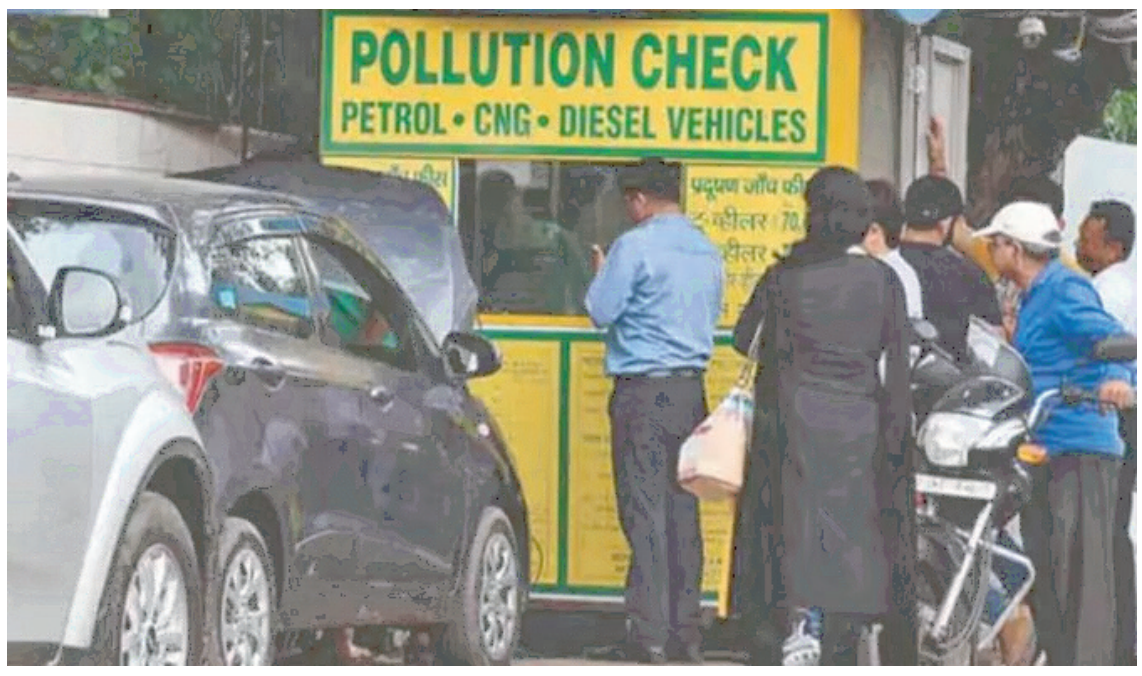

बात यह है कि अस्पताल में गंभीर हालत में कई व्यक्तियों के चल रहे उपचार को देखते हुए, मृत्यु दर बदल सकती है।

जून और अक्तूबर के बीच, राज्य के कैमरों ने कुल 7,432,371 यातायात उल्लंघनों का पता लगाया। इनमें से, अधिकारियों ने 5,829,926 मामलों की समीक्षा की, 2,306,023 मामलों को इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (एकीकृत परिवहन निगरानी प्रणाली) पर अपलोड किया और 2,103,801 उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया। अब तक, सरकार ने जुर्माने के रूप में लगभग 21.5 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हैं।

अक्तूबर में सबसे ज्यादा उल्लंघन के मामले बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना था, जिसकी संख्या 21,865 थी। इसके अलावा, कैमरे ने पीछे बैठने वालों के हेलमेट न पहनने के 16,581 मामले, आगे की सीट पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट की अनदेखी करने के 23,296 मामले, कार चालकों द्वारा सीट बेल्ट न लगाने के 25,633 मामले और मोबाइल फोन के इस्तेमाल के उल्लंघन के 662 मामले रिकॉर्ड किए।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

'वरदान' है ये औषधीय पौधा, चेहरे की झुर्रियों से लेकर जोड़ों के दर्द का रामबाण! कई बीमारियों का भी दुश्मन

मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में आज भी लोग पुरानी परंपरा रीतिरिवाजों से तालुकात रखते हैं. यही वजह है कि दमोह जिले के ज्यादातर घरो के बाहर अशोक का पेड़ दिखाई पड़ता है. वहीं हिंदू शास्त्रों में अशोक के पेड़ का विशेष महत्व बताया गया है.

अशोक का पेड़ लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है. जिस घर में अशोक का पेड़ होता है, वहां शांति, खुशहाली और सुख संपदा का वास होता है. इस पेड़ के पत्तों के उपाय से पति-पत्नी के बीच प्यार भी बढ़ता है.

आयुर्वेद में है विशेष महत्व

वहीं आयुर्वेद की दृष्टि से अशोक का पेड़ एक औषधीय पौधा है, जिसके पत्तों का उपयोग लेप बनाकर करने से जोड़ो का दर्द, चेहरे की झुर्रियां को कम करने के लिए फायदेमंद होता है. यह औषधि पौधा मुंहासो को ठीक करने में मददगार है. इतना ही नहीं डायबिटीज के मरीज इसके पत्तों का सेवन करते हैं तो उनको भी फायदा होता है.

महिलाओं के लिए है वरदान

आयुर्वेद चिकित्सा डॉ दीप्ति नामदेव ने बताया कि अशोक के पौधे की पत्तियों का सेवन करने से डायबिटीज बीमारी से छुटकारा मिलता है. इसके अलावा महिलाओं की त्वचा सम्बंधी उपचार चेहरे की सुंदरता, घुटनों के जोड़ो में दर्द और महिलाओं के लिए यह औषधि पौधा किसी वरदान से कम नहीं है.

नाक से सांस लेना ज्यादा बेहतर है या मुंह से? जानें रनिंग के दौरान कौन सा तरीका है बेस्ट

श्वास अवचेतन है। हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है - यह बस हो जाता है। लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं, तो हममें से कई लोग इसके प्रति सामान्य से अधिक जागरूक हो जाते हैं - कभी-कभी हम अपनी हर सांस के बारे में सोचते हैं। कम और मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के दौरान, हममें से अधिकांश लोग अपनी नाक से सांस लेते हैं और अपने मुंह से सांस छोड़ते हैं। लेकिन व्यायाम जितना अधिक तीव्र होता जाता है, उतना ही हम पूरी तरह मुंह से सांस लेने लगते हैं।

हममें से अधिकांश लोग यह मानेंगे कि गहन व्यायाम के दौरान मुंह से सांस लेना सबसे अच्छी तकनीक है, क्योंकि यह हमारी मांसपेशियों तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचने में मदद देता है। लेकिन सबूत इसके विपरीत दिखाते हैं - और यह कि आपकी नाक से सांस लेना वास्तव में गहन व्यायाम (जैसे दौड़ना) के दौरान उपयोग करने के लिए एक बेहतर तकनीक हो सकती है। अध्ययनों की एक श्रृंखला से पता चला है कि विभिन्न तीव्रता पर व्यायाम करते समय, मुंह से सांस लेने की तुलना में नाक से सांस लेने पर कम ऑक्सीजन का उपयोग होता है। हालांकि यह कोई फ़ायदा नहीं लग सकता है, लेकिन मूल रूप से इसका मतलब यह है कि शरीर कम ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए भी उतनी ही मात्रा में व्यायाम कर सकता है। यह विशेष रूप से अधिक सहनशक्ति वाले एथलीटों के लिए एक वास्तविक लाभ हो सकता है क्योंकि गति को अधिक समय तक बनाए रखना ही सफलता का मूलमंत्र है।

नाक से नहीं खींच सकते ज्यादा ऑक्सीजन

ऑक्सीजन को कार के लिए ईंधन की तरह समझें। एक कार प्रति गैलन जितने कम ईंधन का उपयोग करती है उसकी ईंधन अर्थव्यवस्था उतनी ही बेहतर होती है। यही बात ऑक्सीजन पर भी लागू होती है। चलते हुए पैदल यात्री जितनी कम ऑक्सीजन का उपयोग करेगा, व्यक्ति उतनी ही कम ऊर्जा का उपयोग करेगा (और इसलिए वह उतना ही अधिक किफायती होगा)। इसका मतलब है कि आप जल्दी थके बिना आगे दौड़ने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा, आपकी नाक से सांस लेने से हवा की मात्रा कम हो जाती है। यह समझ में आता है, क्योंकि नाक आपके मुंह से बहुत छोटी होती है, इसलिए आप एक समय में इतनी अधिक ऑक्सीजन नहीं खींच सकते। लेकिन इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि व्यायाम करते समय लोग अपनी नाक से कम बार सांस लेते हैं, जो कम तर्कसंगत लगता है। यहां मुख्य बात यह समझना है कि हवा उच्च दबाव से कम दबाव की ओर जाती है ताकि उसे फेफड़ों में जाने में मदद मिल सके। इसलिए यद्यपि मुंह की तुलना में नाक गुहा में हवा की मात्रा कम होती है, लेकिन दबाव अधिक होता है - जिसका अर्थ है कि हवा श्वसन प्रणाली में अधिक तेज़ी से प्रवेश करती है।

नाक से सांस लेने के हैं ज्यादा फायदे

इसका परिणाम यह होता है कि काम करने वाली मांसपेशियों तक ऑक्सीजन अधिक तेजी से पहुंचाई जा सकती है। प्रति सांस अधिक ऑक्सीजन भी निकलती है, जो बताता है कि एक ही व्यायाम के दौरान मुंह या नाक से सांस लेने पर हृदय गति में कोई अंतर क्यों नहीं होता है। इसलिए कम मात्रा में ऑक्सीजन आने के बावजूद, यह इंगित करता है कि हृदय को इसे मांसपेशियों तक पहुंचाने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि व्यायाम के दौरान नाक से सांस लेने पर हृदय पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। शोधकर्ताओं का यह भी सुझाव है कि नाक से सांस लेने से नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे न केवल फेफड़ों और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचना आसान हो जाता है, बल्कि यह वायुजनित रोगजनकों (जैसे वायरस) को भी रोक सकता है।

व्यायाम के दौरान जागरूक रहने की जरूरत

नाइट्रिक ऑक्साइड रक्तचाप को कम करके और रक्त प्रवाह को अधिक आसानी से मदद करके ऐसा करता है, जिससे काम करने वाली मांसपेशियों तक आवश्यक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि दौड़ते समय आपकी नाक से सांस लेना वास्तव में फायदेमंद हो सकता है। यह आपकी गतिविधियों को अधिक किफायती बनाता है, आपके सांस लेने वाले वायुजनित कणों की मात्रा को कम करता है, व्यायाम करने वाले रक्तचाप को कम करता है और ऑक्सीजन को काम करने वाली मांसपेशियों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचने में मदद करता है। अन्य प्रकार के व्यायामों (जैसे वजन उठाना) के लिए साक्ष्य कम स्पष्ट हैं, जिनमें कम, तीव्र प्रयास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के व्यायाम ऑक्सीजन के अलावा अन्य स्रोतों से ऊर्जा खींचने पर निर्भर करते हैं - जैसे कि हमारी मांसपेशियों में संग्रहीत चीनी (ग्लूकोज)। लेकिन ये चयापचय प्रक्रियाएं, जो व्यायाम के दौरान समाप्त हो जाती हैं, उन्हें ठीक होने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। व्यायाम के बीच में आराम करते समय अपनी नाक से गहरी सांस लेने से इस प्रक्रिया को और अधिक बेहतर तरीके से होने में मदद मिल सकती है। लेकिन हालाँकि यह सब अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक और उत्साहवर्धक लगता है, लेकिन कुछ नकारात्मक बातें भी हैं जिनके बारे में जागरूक होना ज़रूरी है। व्यायाम के दौरान केवल अपनी नाक से सांस लेना एक बहुत ही सीखी जाने वाली प्रक्रिया है।

इसे तुरंत लागू नहीं किया जाना चाहिए

यदि आप इसे प्रशिक्षण के बिना शुरू करते हैं, तो इससे श्वायु भूखश पैदा हो सकती है - एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत प्रत्येक सांस के अंत में थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बरकरार रहती है। इससे असुविधा और हाइपरवेंटिलेशन हो सकता है। किसी भी चीज़ की तरह, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। अपनी नाक से सांस लेना सीखते समय, सुनिश्चित करें कि आप हवा को जबरदस्ती अंदर न डालें। कोशिश करें और इस प्रक्रिया में आराम करें। सुनिश्चित करें कि आपकी जीभ आपके मुंह के शीर्ष पर है, क्योंकि इससे जबड़े और चेहरे की मांसपेशियों को आराम मिलता है जिससे आपकी नाक के माध्यम से गहरी सांस लेना आसान हो जाता है। हो सकता है कि आप शुरुआत में अपनी नाक और मुंह से सांस लेने के बीच बदलाव करना चाहें, जब तक कि आपको पूरी तरह से अपनी नाक से सांस लेने की आदत न हो जाए। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, प्रक्रिया उतनी ही अधिक अवचेतन होती जाएगी। व्यायाम करते समय नाक से सांस लेना बहुत प्रभावी हो सकता है। बस अभ्यास करना सुनिश्चित करें और नुकसान से बचने के लिए अपने शरीर को समायोजित होने का समय दें।

10 जोखिम कारक जो बढ़ा देते हैं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, बदल लें ये आदतें भी

कई जोखिम कारक होते हैं, जिसके कारण महिलाओं में स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होने की फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, अधिक उम्र होना आदि. इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं, जिन्हें आपको जानकर लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने की जरूरत हो सकती है.

अक्टूबर महीने को विश्व भर में 'ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ' के रूप में मनाया जाता है. इस पूरे महीने कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है. इसके लक्षणों, कारणों के बारे में जनकारी दी जाती है, ताकि महिलाएं समय रहते स्तन कैंसर (Breast Cancar)का इलाज शुरू करा कर अपने जीवन को बचा सकें. दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले कैंसर में स्तन कैंसर सबसे कॉमन है. हर साल लाखों महिलाएं इससे ग्रस्त होती हैं. आखिर किन कारणों से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, इसके रिस्क फैकटर्स क्या हैं, आइए जानते हैं'

कैसे होता है ब्रेस्ट कैंसर?

कैंसरसेंटर डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार, महिलाओं में स्तन कैंसर तब होता है, जब ब्रेस्ट की कोशिकाओं में डीएनए उत्परिवर्तित (Mutate) या परिवर्तित होने लगता है. इससे कोशिकाओं में वृद्धि और विभाजन को कंट्रोल करने वाले खास कार्य अक्षम हो जाते हैं. कुछ मामलों में, ये उत्परिवर्तित कोशिकाएं मर जाती हैं या प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उन पर हमला किया जाता है. लेकिन कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली से बच जाती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, जिससे ब्रेस्ट में ट्यूमर बन जाता है.

ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क फैक्टर्स

कई जोखिम कारक हैं, जो महिलाओं में स्तन कैंसर होने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं. इसमें कुछ ऐसे जोखिम कारक शामिल हैं, जिन्हें आप खुद से बदल नहीं सकते हैं, जैसे परिवार में ब्रेस्ट कैंसर होने की हिस्ट्री, जेनेटिक्स, अधिक उम्र होना. हालांकि, कुछ ऐसे भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन्हें रोककर ब्रेस्ट कैंसर के विकास की संभावनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है. हालांकि, कई बार जिन महिलाओं में कैंसर होने का जोखिम रहता है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, वहीं जिनमें रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल नहीं होते, वे इस घातक कैंसर की चपेट में आ जाती हैं. हालांकि, हेल्दी लाइफस्टाइल को चुनकर इस गंभीर बीमारी से काफी हद तक खुद को सुरक्षित रख सकती हैं. कुछ अन्य रिस्क फैक्टर्स जो ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार हैं-

-55 या इससे अधिक उम्र होने पर ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है.

– ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को बढ़ाने के लिए जेंडर भी है एक मुख्य कारण है. पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये बीमारी काफी अधिक होती है.

– जो महिलाएं प्रतिदिन एल्कोहल का सेवन करती हैं, उनमें भी स्तन कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है.

– यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो इससे ना सिर्फ डायबिटीज, हार्ट डिजीज होता है, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा भी बना रहता है.

-जो महिलाएं शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहती हैं या कम चलती-फिरती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का जोखिम काफी अधिक होता है. ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करें. ब्रिस्क वॉक, रनिंग, जॉगिंग आदि करें. जितना ही आप फिजिकली एक्टिव रहेंगी, उतनी ही फिट और हेल्दी रह सकती हैं.

– कई बार पीरियड्स 12 साल की उम्र से पहले होने और 55 साल की उम्र के बाद मेनोपॉज होने के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर होने का जोखिम कुछ महिलाओं में बढ़ जाता है.

– मां बनने के बाद यदि आपने अपने शिशु को स्तनपान नहीं कराया, तो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने की संभावना बढ़ सकती है. ऐसे में शिशु के जन्म के बाद 6 महीने जरूर ब्रेस्टफीड कराएं.

– यदि परिवार में ब्लड रिलेशन में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो इस घातक बीमारी के होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है.

– कई बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी ब्रेस्ट कैंसर रिस्क को बढ़ा सकते हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव का सेवन, बर्थ कंट्रोल शॉट, बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट, बर्थ कंट्रोल स्किन पैचेज आदि के अधिक इस्तेमाल से भी इस कैंसर के होने का रिस्क बढ़ सकता है.

प्रदूषण की वजह से कहीं छुट्टी तो कहीं चलेंगी ऑनलाइन क्लासेज, जानिए दिल्ली-एनसीआर में क्या हैं दिशा-निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। राजधानी में कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। प्रदूषण की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज चलाने का निर्देश दिया गया है। गुरुग्राम फरीदाबाद गाजियाबाद नोएडा में भी राज्य सरकारों ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया है।

दिल्ली/एनसीआर। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। राजधानी में कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। प्रदूषण की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा एनसीआर के शहरों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा) में भी राज्य सरकारों ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया है।

दिल्ली में स्कूलों को लेकर क्या है आदेश?

AAP सरकार के अनुसार, दिल्ली के स्कूल 10 नवंबर 2023 तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया है कि विद्यालय ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के बारे में नियम के अनुसार सभी शिक्षकों को स्कूल में आना होगा और वहां से वे विभिन्न कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने घर से ही क्लासेज को ज्वॉइन करेंगे। यह फैसला प्रदूषण के लिए निर्धारित ग्रैप-4 पाबंदियों के तहत लिया गया है।

10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाने की छूट

इसके साथ ही 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कुछ ही समय बचा होने का कारण इन दोनों ही कक्षाओं के लिए ऑफलाइन क्लास का ऑप्शन स्कूलों को प्रदान किया गया है। इसके अनुसार अगर स्कूल चाहें तो 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को विद्यालय में बुला सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। यह विद्यालय पर निर्भर करेगा कि वे किस प्रकार से स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं।

गाजियाबाद और नोएडा के लिए नियम

गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन ने सभ स्कूलों से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया है। यह आदेश 10 नवंबर तक जारी रहेगा। यह आदेश ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज-4 लागू होने पर दिया गया है।

फरीदाबाद में पांचवी तक का अवकाश

वायु प्रदूषण को देखते हुए जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की 12 अक्टूबर तक अवकाश की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह से वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खतरनाक है। बाकी कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को स्कूल आना होगा।

गुरुग्राम में चलेंगी ऑनलाइन क्लासेज

गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने प्रदूषण बढ़ने पर पांचवी कक्षा तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रदूषण से बच्चों के बचाव के लिए इस संदर्भ में जारी आदेशों में प्री स्कूल, प्री-प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए स्कूल प्रबंधकों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के आदेश दिए गए हैं।

बस मार्शलों के धरने पर गुरुद्वारे का लंगर शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। 'बस मार्शल भूख हडताल पर, गुरूद्वारे का लंगर भी बंद' शीर्षक से परिवहन विशेष में 2 नवंबर को छपी खबर का असर हो गया है। गुरूद्वारे की लंगर सेवा सोमवार से फिर शुरू कर दी गई है। इस बावत धरने पर बैठे मार्शल आदित्य ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि तमाम मार्शलों ने गुरू सेवकों द्वारा गुरूद्वारे की लंगर सेवा शुरू करने के लिए गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी समेत अखबार का धन्यवाद और आभार जताया है।

धर्म और रिलीजन पूरी तरह से अलग, हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका; दिल्ली और केंद्र सरकार ये निर्देश देने की मांग

भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने धर्म और रिलीजन के बीच अंतर करने और प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इस विषय पर एक अध्याय शामिल करने का केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अश्विनी ने कहा कि इससे जनता को शिक्षित करना और धर्म-आधारित घृणा और नफरत भरे भाषणों को नियंत्रित किया जा सकेगा।

नई दिल्ली। भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने धर्म और रिलीजन के बीच अंतर करने और प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इस विषय पर एक अध्याय शामिल करने का केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अश्विनी ने कहा कि इससे जनता को शिक्षित करना और धर्म-आधारित घृणा और नफरत भरे भाषणों को नियंत्रित किया जा सकेगा।

याचिका में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेजों में धर्म का उचित अर्थ इस्तेमाल करने के लिए भी सरकारों को निर्देश देने की भी मांग की गई है। उपाध्याय के अनुसार, रिलीजन का अर्थ धर्म न होकर पंथ या संप्रदाय है।

धर्म और रिलीजन पूरी तरह से अलग

उन्होंने तर्क दिया कि धर्म और रिलीजन पूरी तरह से अलग-अलग है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी न केवल जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों में धर्म शब्द का उपयोग रिलीजन के पर्याय के रूप में करते हैं। उपाध्याय ने याचिका में कहा कि धर्म एक आदेश देने वाला सिद्धांत है, जो किसी के विश्वास या पूजा के तरीकों से स्वतंत्र है।

संतों ने अलग-अलग समय में दिया मार्गदर्शन

याचिका में कहा गया कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय में पैदा हुए अलग-अलग संतों ने अलग-अलग भाषाएं बोलकर लोगों को अपने तरीके से धार्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन किया। सच्चे संत होने के नाते उन्होंने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार धर्म का वर्णन किया है।

सिंगर हनी सिंह अपनी पत्नी से हुए अलग, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंजूर किया तलाक

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को गायक और रैपर हनी सिंह और उनकी पत्नी के तलाक को मंजूर कर लिया। पिछले साल सितंबर में हनी सिंह ने अपनी पत्नी को एक करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट भी सौंपा था। फैसला सुनाने से पहले न्यायाधीश ने सिंह से पूछा कि क्या वह अब भी अपनी पत्नी के साथ रहने की कोशिश करना चाहते हैं।

दक्षिणी दिल्ली। साकेत कोर्ट ने मंगलवार को गायक और रैपर हनी सिंह और उनकी पत्नी के तलाक को मंजूर कर लिया। फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश परमजीत सिंह ने सिंह और उनकी पत्नी के बीच ढाई साल पुराने मुकदमे को समाप्त करते हुए दोनों पक्षों को तलाक की डिक्री दे दी।

घरेलू हिंसा के लगाए थे आरोप

हनी सिंह की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। आरोप लगाया था कि वह डर में जी रही थी, चूंकि हनी सिंह और उसके परिवार द्वारा उस पर मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक हिंसा की गई थी। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने पर सारे आरोप वापस ले लिए थे।

पत्नी को एक करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा

निपटारे से जुड़ी शर्तें सीलबंद लिफाफे में रखी गई थीं। पिछले साल सितंबर में हनी सिंह ने अपनी पत्नी को एक करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट भी सौंपा था। फैसला सुनाने से पहले न्यायाधीश ने सिंह से पूछा कि क्या वह अब भी अपनी पत्नी के साथ रहने की कोशिश करना चाहते हैं। गायक ने उत्तर दिया कि साथ रहने का कोई और मौका नहीं है।

हिंदुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान-2023 संपन्न

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। दिल्लीः रिठाला के विधायक महेंद्र गोयल ने करवा चौथ के मौके पर सुहागिनों के हाथों में फ्री मेंहदी लगाने का मेला लगाया। अवंतिका सेक्टर -1, स्थित विधायक कार्यालय के अंदर और बाहर प्रांगण में सुहागिनों ने अपने दोनों हाथों में मेंहदी लगवाई और विधायक महेंद्र गोयल को सुहागिनों ने फ्री मेहंदी सेवा के लिए दुआएं और आशीष से नवाजा।

इस बावत विधायक महेंद्र गोयल ने बताया कि करीब दो दर्जन कमर्शियल मेंहदी लगाने वाली एक्सपर्ट को इस काम के लिए लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे से देर शाम तक सुहागिनों को फ्रिरी मेहंदी लगाने का कार्यक्रम जारी रहेगा। इस विशेष प्रबंध को अनुशासित करने के लिए स्वंम विधायक महेंद्र गोयल के अलावा आप कार्यकर्ताओ की टीम में रिठाला विसभा अध्यक्ष सत्यवान राणा, शुभम-- त्रिपाठी, विजय विहार वार्ड अध्यक्ष उमेश गुप्ता,विनय गुप्ता,पीयूष, जय पारिख,कार्यक्रम संयोजिका मोनिका गर्ग, के अलावा रेखा,छाया तिवारी,गीता पॉल, रमा कौशिक आदि व्यवस्था में मौजूद थी। विजय विहार वार्ड अध्यक्ष उमेश गुप्ता, एवं अध्यक्ष सत्यवान राणा ने बताया कि देर शाम तक तीन सौ - चार सौ से अधिक सुहागिनों को फ्री मेंहदी लगाई गई। मेंहदी के अलावा सभी सुहागिनों के लिए खान-पान की व्यवस्था भी की गई थी।

दिल्ली-एनसीआर में अभी प्रदूषण से राहत नहीं, चारों ओर धुंध ही धुंध; जानें कितना रहा AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार, मंगलवार को भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सुबह के वक्त कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। गुरुवार तक दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिलने के संकेत हैं। वहीं ऑड-ईवन को लागू किया जा रहा है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैंबर बनी हुई है। ऐसे में दिल्लीवासियों की सांसों पर संकट बरकरार है। दिवाली से पहले राहत मिलती हुई भी नहीं दिख रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार, मंगलवार को भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सुबह के वक्त कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। ऐसे में लोगों को मौसम के मेहरबान होने का इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार जमीन पर योजनाएं उतार रही है। ऑड-ईवन को लागू किया जा रहा है। अभी भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में वायु प्रदूषण सूचकांक 400 से 500 के बीच बना हुआ है। कई हिस्सों में पीएम2.5 खतरनाक स्तर 500 से भी ऊपर चला गया है। मौसम निगरानी एजेंसियों ने इसे 'गंभीर' माना है।

सोमवार को दिल्ली में इतना रहा एक्यूआई

बीते दिन भी दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित रही। सोमवार को यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 421 दर्ज किया गया। हालांकि, रविवार के मुकाबले 33 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। जहांगीरपुरी और वजीरपुर समेत 24 इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सुबह से ही स्मॉग की चादर छाई रही। ऐसे में यही स्थिति बृहस्पतिवार तक बने रहने का अनुमान है। एनसीआर में दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा की हवा अधिक प्रदूषित रही। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का चौथा चरण लागू है।

दिल्ली का ये इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित

दिल्ली में सोमवार को 24 इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। जबकि रविवार के मुकाबले चार इलाकों में गिरावट दर्ज की गई। पांच इलाकों में हवा बेहद खराब रही। इसमें जहांगीरपुरी में 458, वजीरपुर में 455, पटपड़गंज में 453, पंजाबी बाग में 450, आरके पुरम में 447, रोहिणी में 445 एक्यूआई दर्ज किया गया। मुंडका में 439, आनंद विहार में 433 समेत कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। डीटीयू में 398 व जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 362 समेत छह इलाकों में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में रहा।

दिल्ली वालों को बारिश का इंतजार

दिल्ली में प्रदूषण से राहत के लिए मौसम का इंतजार शहर के लोगों को करना पड़ेगा। मौजूदा मौसमी दशाएं प्रदूषण को बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा मौसम में प्रदूषण तत्व छट नहीं पा रहे हैं, ऐसे में यदि मौसम करवट ले तो एक पल में प्रदूषण खत्म हो सकता है। स्थिति सुधरने के लिए मौसम के अनुकूल होने का इंतजार करना होगा। इस बीच आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे।

दिल्ली में ऑड ईवन निमय

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। इसी बीच सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवायल में उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे थे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में ऑड ईवन लागू होगा। 13 से 20 नवंबर के बीच इसे लागू किया जाएगा। ऑड-ईवन यातायात नियम एक ऐसी प्रणाली है, जिसके तहत ऑड नंबर पर खत्म होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को सप्ताह के ऑड दिनों पर चलने की अनुमति होती है। ईवन नंबर पर समाप्त होने वाली पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को सप्ताह के अन्य वैकल्पिक दिनों में सड़कों पर चलने की अनुमति है। पूर्व में रविवार को सभी वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रखा गया है।

गोरक्षकों और गोतस्करों में मुठभेड़ एक गिरफ्तार; 25 गाय बरामद

केएमपी एक्सप्रेस-वे पर बिलासपुर में गोरक्षकों और गोतस्करों में मंगलवार सुबह मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोतस्करों की तरफ से गोरक्षकों पर फायरिंग की गई। गोरक्षकों से बचने के लिए एक किलोमीटर तक गोतस्करों ने अपना ट्रक डिवाइडर पार ले जाकर उल्टी दिशा में भी दौड़ाया। ट्रक से मेवात ले जाई जा रही 25 गायें बरामद की गईं। गायों को ठूंस-ठूंस कर भरे जाने से दो की मौत हो गई।

परिवहन विशेष न्यूज

गोरक्षकों और गोतस्करों में मुठभेड़
गोरक्षकों ने बरामद की 25 गायें

गुरुग्राम। केएमपी एक्सप्रेस-वे पर बिलासपुर में मंगलवार सुबह गोरक्षकों ने करीब तीन किलोमीटर तक पीछा करने के बाद गोतस्करों के ट्रक को पकड़ लिया। करीब एक किलोमीटर तक गोतस्करों ने अपना ट्रक डिवाइडर पार ले जाकर उल्टी दिशा में भी दौड़ाया।

गोरक्षकों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को रोक लिया और एक आरोपित को पकड़ा। ट्रक से गोकशी के लिए मेवात ले जाए जा रहे 28 गोवंशी बरामद किए गए। ठूंस-ठूंस कर भरे जाने से दो गोवंशी की मौत हो गई।

पीछा करने पर की फायरिंग: पुलिस

बिलासपुर थाना पुलिस के अनुसार गुरुग्राम गोरक्षकों की टीम को 28 गोवंशियों से भरे एक ट्रक के उत्तर प्रदेश के बागपत की तरफ से केएमपी एक्सप्रेस-वे के रास्ते मेवात जाने की सूचना मिली। इस पर टीम ने काउ टास्क फोर्स के साथ बिलासपुर क्षेत्र में कई जगह नाकेबंदी की। बिलासपुर में केएमपी पर तेज रफ्तार ट्रक आता दिखाया, उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रक नहीं रुका। इसके बाद काउ टास्क फोर्स और गोरक्षकों की टीम ने तीन किलोमीटर तक ट्रक का पीछा किया।

बताया जाता कि इस दौरान ट्रक में मौजूद तस्करों ने हवाई फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। करीब दो किलोमीटर के बाद गोतस्करों ने अपना ट्रक डिवाइडर के दूसरी तरफ ले जाकर उल्टी दिशा में दौड़ाना शुरू किया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। इस दौरान ट्रक का अगला टायर भी पंचर हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद गोरक्षकों की टीम ने ट्रक रोककर ट्रक डाइवर को पकड़ लिया। उसकी पहचान नूंह के अलावलपुर निवासी नफीस के रूप में की गई। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके साथ पांच और लोग भी मौजूद थे। मौका मिलने पर सभी फरार हो गए।

गायों को मेवात ले जा रहे थे तस्कर

तस्कर गायों को भरकर गोकशी के लिए मेवात ले जा रहे थे। ट्रक में 28 गोवंशियों को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था। इनमें दो गोवंशी मृत अवस्था में मिले। डाक्टरी जांच के बाद काउ टास्क फोर्स ने सभी गोवंशियों को गोशाला भेज दिया। बिलासपुर थाना पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक को जब्त कर लिया गया।

ट्रक के साथ चल रही क्रेटा गाड़ी में थे तस्कर

बताया जाता है कि जिस ट्रक में गोवंशियों को जे जाया जा रहा था। उसके आगे-आगे एक क्रेटा गाड़ी चला रही थी। इसमें चार तस्कर मौजूद थे। आगे-आगे चलकर तस्कर ट्रक ड्राइवर को पुलिस की सूचना दे रहे थे। जैसे ही उन्हें गोरक्षकों की टीम का पता चला तो उन्होंने वहां से भागने का प्लान बनाया।

उन्हीं के कहने पर ट्रक ड्राइवर ने उल्टी दिशा में ट्रक दौड़ाया। इसके बाद मौका पाते ही क्रेटा सवार तस्कर भाग निकले। क्रेटा गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी।

एल्विश यादव को पुलिस ने भेजा नोटिस, योगी के मंत्री बोले- कानून से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है...

रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई के मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए बिग बॉस विनर एल्विश यादव को नोटिस भेजा है। नोएडा जोन के डीसीपी हरीश चंदर ने कहा कि वह जल्द पेश होकर जांच में सहयोग करें। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री ने कहा कि कानून से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है।

नोएडा। रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई के मामले में मंगलवार को पुलिस ने पूछताछ के लिए बिग बॉस विनर एल्विश यादव को नोटिस भेजा है। नोएडा जोन के डीसीपी हरीश चंदर ने कहा कि वह जल्द पेश होकर जांच में सहयोग करें।

एल्विश यादव पर क्या बोली योगी सरकार

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने एल्विश यादव से जुड़े मामले की जांच पर कहा कि कानून अपना काम करेगा। कोई भी सेलिब्रिटी, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, कानून से बड़ा नहीं है।

छह लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस

बता दें कि नोएडा पुलिस ने सेफरन वेडिंग विला में रेव पार्टी के लिए सांप के जहर की सप्लाई करने वाले गिरोह को पकड़ा है। इसके बाद इस मामले में बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव समेत छह लोगों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

राजस्थान पुलिस ने भी की थी पूछताछ

एफआईआर के बाद एल्विश यादव को राजस्थान की कोटा पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि वाहनों की चेकिंग के दौरान एल्विश से पूछताछ की गई। एल्विश के बारे में पता चला कि उस पर नोएडा में केस दर्ज है। इसके चलते नोएडा पुलिस को सूचना दी गई, फिर वहां से बताया कि वह अभी वांछित नहीं और मामले में जांच चल रही है। इसके चलते उसे छोड़ दिया गया।

सेल्स मैनेजर से छेड़छाड़, विरोध करने पर पीटा... फिर किया अगवा करने का प्रयास

बाइक सवार चार युवकों ने सरेराह रियल एस्टेट कंपनी की सेल्स मैनेजर से छेड़छाड़ की और अगवा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर पीड़िता और उनके दो सहकर्मियों को पीटा। घटना सोमवार शाम प्रताप विहार इलाके की है। लोगों ने एक आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान युवती ने बताया कि वह रोजाना की तरह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थीं।

गाजियाबाद। बाइक सवार चार युवकों ने सरेराह रियल एस्टेट कंपनी की सेल्स मैनेजर से छेड़छाड़ की और अगवा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर पीड़िता और उनके दो सहकर्मियों को पीटा। घटना सोमवार शाम प्रताप विहार इलाके की है। लोगों ने एक आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धार्थ विहार स्थित एक प्रोजेक्ट में कार्यरत युवती ने बताया कि वह रोजाना की तरह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थीं। सिद्धार्थ विहार चौराहा पार करने के बाद बाइक पर जा रहे दो सहकर्मियों को रोककर कहा कि आगे सुनसान इलाका है।

पत्नी को बुरा-भला तो बचपन के दोस्त को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

शराब पीने के दौरान पत्नी को बुरा-भला कहने पर युवक ने बचपन के दोस्त की हत्या कर दी। घटना Ghaziabad Crime News सोमवार रात महरौली की है जिसके बारे में पुलिस को मंगलवार तड़के पता चला। थाना वेव सिटी पुलिस ने सतेंद्र चौधरी उर्फ सोमी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपित दीपक उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद। शराब पीने के दौरान पत्नी को बुरा-भला कहने पर युवक ने बचपन के दोस्त की बलकटी से वार कर हत्या कर दी। घटना सोमवार रात महरौली की है, जिसकी पुलिस को सूचना मंगलवार तड़के मिली।

गांव का ही रहने वाला आरोपित गिरफ्तार

थाना वेव सिटी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। कार्यवाहक एसीपी वेव सिटी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मृतक की पहचान महरौली के सतेंद्र चौधरी उर्फ सोमी के रूप में हुई है। गांव में ही रहने वाले उसके दोस्त दीपक उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है।

शराब के नशे में हुई कहासुनी

दीपक सोमवार रात करीब नौ बजे सतेंद्र को घर से बुलाकर अपने फार्म हाउस पर लाया था। दोनों यहां अक्सर पार्टी करते थे। दीपक ने पुलिस को बताया कि सोमवार रात को शराब पीने के दौरान सतेंद्र ने उसकी पत्नी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर लांछन लगाने लगा। विरोध पर दोनों में कहासुनी हो गई।

गुस्से में उसने फार्महाउस में रखी बलकटी उठाई और सतेंद्र के सिर, चेहरा, गर्दन व सीने पर कई वार कर दिए। पुलिस के मुताबिक हत्या करीब साढ़े 12 बजे हुई, जिसके बाद दीपक ने एंबुलेंस को भी फोन किया। एंबुलेंस चालक पहुंचा तब तक सतेंद्र की मौत हो चुकी थी।

एसीपी ने बताया कि एंबुलेंस चालक ने पुलिस को फोन किया था, जिसके बाद दीपक मौके से फरार हो गया। दीपक को गांव के पास से ही तड़के गिरफ्तार कर लिया था। पोस्टमार्टम के शव स्वजन को सौंप दिया है। सतेंद्र के भाई अरविंद ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाई के हाथ पर ही उसका नाम लिखा था।

इसके बाद भी शव को मोर्चरी भेजकर सूचना मिलने के करीब चार घंटे बाद उन्हें बताया गया। दीपक की पत्नी के बारे में सतेंद्र द्वारा टिप्पणी करने की बात को भी बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने साजिशन हत्या का आरोप लगाया है।

नोएडा वासियों के काम की खबर, पानी का बकाया बिल वसूलने के लिए एकमुश्त समाधान योजना ला रहा प्राधिकरण

अवैध कनेक्शन पर लगने वाला जुर्माना पर 40 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस एलआइजी श्रमिक कुंज व ग्रामीण संयोजनों पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी। एक अप्रैल को स्वत ही समाप्त हो जाएगी। योजना के तहत 31 दिसंबर 2023 तक बकाया के ब्याज पर जनवरी 2024 में 40 प्रतिशत फरवरी में 30 और मार्च में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण बकाया पानी का बिल को वसूलने के लिए एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लेकर आ रहा है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2023 तक बकाया के ब्याज पर जनवरी 2024 में 40 प्रतिशत, फरवरी में 30 और मार्च में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। समस्त प्रकार के अनधिकृत संयोजनों में कम से कम पांच साल से स्थाई जल प्रभार, स्थाई पंजीकरण और इकाई कार्यशील घोषित होने की तिथि में जो भी पहले है। अवैध कनेक्शन पर लगने वाला जुर्माना पर 40 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस, एलआइजी, श्रमिक कुंज व ग्रामीण संयोजनों पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी। एक अप्रैल को स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

143.6 करोड़ का पानी पी गए 267 आवंटी

नोएडा में जल के बड़े बकाएदार भी है। जल खंड-1, 2, 3 को मिलाकर कुल 267 आवंटियों पर 143.6 करोड़ रुपये बकाया है। सभी आवंटी में पांच लाख से ज्यादा बकाया की श्रेणी में आते है। इसके अलावा 21 अन्य प्रकरणों में करीब 42.30 करोड़ रुपये की आरसी जारी की गई है। इनकी वसूली भू राजस्व के हिसाब से की जाएगी। यह बकाया प्राधिकरण सभी श्रेणी की संपत्तियों जिसमें वाणिज्यिक, संस्थागत, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक और आवासीय शामिल है। जल खंड-एक की बात करे जो सबसे ज्यादा बकाएदार आवंटी औद्योगिक क्षेत्र से हैं।

चुनावी बेला में राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा के मायने क्या हैं?

मृत्युंजय दीक्षित

तमिलनाडु के द्रमुक नेताओं द्वारा सनातन हिंदू समाज के उन्मूलन की बात पर गांधी परिवार पूरी तरह से मौन साध गया। अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी अपना सारा काम छोड़कर केदारनाथ धाम पहुंच गये। सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की बात कर रहे हैं।

भारतीय राजनीति में मुस्लिम तुष्टिकरण को चुनाव जीतने का मन्त्र मन जाता रहा है किन्तु 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या पर मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिए जाने के बाद स्थितियों में बड़ा बदलाव आया है।

कुछ वर्ष पूर्व तक भरतीय जनता पार्टी की ओर से नारा लगाया जाता था, "रामलला हम आयेंगे मंदिर वहीं बनायेंगे" और विरोधी दल पलटवार करते हुए कहते थे, "रामलला हम आयेंगें मंदिर वहीं बनायेंगें किंतु तारीख नहीं बतायेंगे"। इस चुनाव में सब कुछ परिवर्तित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद अयोध्या नगरी में दिव्य-भव्य गगनचुम्बी राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है, रामलला के विराजमान होने की तिथि भी आ गयी है। आगामी 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्रीराम अपने अस्थायी मंदिर से नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं।

जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं अब वहां पर भाजपा के सभी स्टार प्रचारक अयोध्या की बात कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में श्री राम मंदिर का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिसके कारण वहां कांग्रेस पार्टी असहज महसूस कर रही है क्योंकि भापजा की ओर से अब केवल यह कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस ही रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़े नेता तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता जनार्दन को अयोध्या दर्शन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उदघाटन कर रहे हैं। अतः छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना लाई जायेगी ताकि छत्तीसगढ़ के लोग राम मंदिर का दर्शन कर सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण देश में रामराज्य का आरम्भ होगा, जहां जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में अपने साढ़े नौ साल के दौरान योजनाओं के माध्यम से राम राज्य की नींव रखी है। यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के तमाम दिग्गज नेता धुधांधार प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए ईसाई मिशनरीज जहां हिंदू समाज का सरकारी सहयोग के बल पर धर्मांतरण करा रही हैं तो वहीं हिंदू मुस्लिम जिहाद से भी आतंकित हो रहे हैं। राज्य में धर्मांतरण की रोकथाम के लिए भाजपा उत्तराखंड व यूपी की तरह धर्मांतरण की रोकथाम के लिए एक व्यापक कानून लाने की बात भी कह रही है।

राजस्थान में भी भाजपा की ओर से समग्र हिन्दुत्व की विचारधारा व उसके विकास को समाहित करते हुए चुनाव प्रचार किया जा रहा है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का बहुत महत्व है और जनसंख्या के आधार पर कुछ सीटों पर वह असरकारी भी है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी वहां भी स्टार प्रचारक हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पूजन करने के बाद अपना अभियान प्रारम्भ किया है। योगी जी ने अपना चुनाव अभियान अजमेर में उसी जगह से प्रारम्भ किया जहां पर प्रशासन ने 300 साल पुराने एक शिव मंदिर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था।

अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी बता दी गई है। मंदिर उद्घाटन की तिथि बता दिये जाने के बाद भी सेक्युलर दलों में काफी तनाव है और यही कारण है कि उनकी ओर से भी लगातार अजब-गजब प्रकार के बयान आ रहे हैं। जहाँ एक ओर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के कारण मुस्लिम समाज को भड़काने का अथक प्रयास किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, सपा, बसपा सहित आप पार्टी के लोग अब कहने लगे हैं कि "राम तो सभी के हैं"।

राहुल गांधी चले केदारनाथ- विधानसभा चुनावों में भाजपा की आक्रामक रणनीति और चुनावों मे कांटे की टक्कर को देखते हुए कांग्रेस गहरे दबाव मे आ गई है और यही कारण है कि जो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदू बनाम हिंदुत्व और तपस्वी बनाम पुजारी में घृणित और विकृत मानसिकता के साथ भेद पैदा कर रहे थे वही अब अपने आप को उदार हिंदू दिखाते हुए केदारनाथ धाम जाकर राजनैतिक विश्लेष्कों को व हिंदू जनमानस को प्रभावित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। सच तो ये है कि राहुल गांधी ने केदारनाथ दौरे से स्वयं को ही कई प्रश्नों के चक्रव्यूह में फंसा लिया है क्योंकि यह वही राहुल गांधी हैं जो विदेशों में जाकर भी हिंदू धर्म का अपमान करते रहे हैं और मंदिरों के विषय में विकृत बयानबाजी करते रहे हैं। राहुल गांधी का अभी तक मानना रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां शक्तिहीन हैं। वह यह बयान भी दे चुके हैं कि हिंदू लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। राहुल गांधी हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए जातिगत जनगणना का अभियान भी चला रहे हैं।

जब ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्षकारों ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था तब कांग्रेस उसे फव्वारा बता रही थी। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए लगातार बाधा डाली और उन्हें भगवान राम व रामचरित मानस को काल्पनिक बताकर हिंदू समाज का हर क्षण अपमान किया।

तमिलनाडु के द्रमुक नेताओं द्वारा सनातन हिंदू समाज के उन्मूलन की बात पर गांधी परिवार पूरी तरह से मौन साध गया। अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी अपना सारा काम छोड़कर केदारनाथ धाम पहुंच गये। सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महादेव एप का विवाद चल रहा है जिस पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घोटालेबाजों ने महादेव को भी नहीं छोड़ा संभवतः उनकी इसी बात का असर हुआ और राहुल गांधी केदारनाथ धाम पहुंच गये। यह भी कहा जा रहा है कि विधान सभा चुनावों में अभी तक कांग्रेस की गारंटियों का कोई ऐसा असर नहीं दिख रहा है यही कारण है कि राहुल गांधी हिंदू समाज की आंखों में धूल झोंकने के लिए केदारनाथ धाम पहुंच गये हैं। सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हो जाने के बाद कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर आ गयी और उसे बयान देना पड़ा कि यह राहुल की निजी आध्यात्मिक यात्रा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदू व सनातन धर्म को लेकर पूरी तरह से भ्रमित रहती है।

ज्ब भी चुनाव आते है कांग्रेसी नेताओं को मंदिर याद आ जाते है। कर्नाटक चुनावों में भी प्रियंका और राहुल गांधी मंदिर दर्शन करने गये थे। कर्नाटक कांग्रेस ने जय बजरंगबली नारे के जवाब में एक हजार हनुमान मंदिर बनवाने का वादा किया था किंतु अभी तक वहाँ केवल मुस्लिम तुष्टिकरण चल रहा है। कांगेस हिंदू समाज के प्रति दोहरा रवैया अपनाती है और सत्ता हथियाते ही मुस्लिम तुष्टिकरण पर उतारू हो जाती है।

राहुल गांधी ऐन चुनाव से पूर्व केदारनाथ गये हैं वह अभी तक केवल दो बार ही यहां आये हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा व भक्ति है और वह प्रधानमंत्री बनने के बाद छह बार केदारनाथ आ चुके हैं और उनके नेतृत्व में यहां पर काफी विकास कार्य प्रगति चल रहे है। हिंदू जनमानस यह बात अब अच्छी तरह से जान गया है कि राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस महज ढोंग व नाटक कर रही है। कांग्रेस ने अभी तक मन से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का स्वागत नहीं किया है। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की तरह उनके मंदिर दर्शन भी संदिग्ध ही हैं।

KTM 390 Adventure vs BMW G 310 GS: कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में कौन बेहतर?

भारत में बिक्री के लिए मौजूदा KTM 390 एडवेंचर 3.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर उपलब्ध है। उम्मीद है कि मोटरसाइकिल का अपडेटेड संस्करण 3.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं BMW G 310 GS एडवेंचर मोटरसाइकिल 313 सीसी सिंगल-सिलेंडर और वॉटर-कूल्ड इंजन द्वारा संचालित होती है। ये एडवेंचर मोटरसाइकिल 3.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है।

नई दिल्ली। हाई-परफॉरमेंस बाइक निर्माता कंपनी KTM ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर KTM 390 Adventure को नए अवतार में पेश किया है। अपडेटेड केटीएम 390 एडवेंचर मोटरसाइकिल को इस साल के अंत में या 2024 की शुरुआत में भारतीय बाजार के अंदर लॉन्च किया जाएगा।

बदलाव की बात करें, तो इसके फ्रंट को अपडेट किया गया है। इसके अलावा इसे आउटगोइंग मॉडल के रूप में सिल्हूट और डिजाइन के साथ मैकेनिकल मोर्चे पर भी समान विशिष्टताओं के साथ पेश किया गया है। अपडेटेड 390 एडवेंचर को दो नए रंग विकल्प मिले हैं, इसमें एडवेंचर व्हाइट और एडवेंचर ऑरेंज सामिल है। KTM 390 Adventure भारतीय बाजार में BMW G 310 GS को टक्कर देगी। आइए, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं।

कीमत

भारत में बिक्री के लिए मौजूदा KTM 390 एडवेंचर 3.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर उपलब्ध है। उम्मीद है कि मोटरसाइकिल का अपडेटेड संस्करण 3.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर लॉन्च किया जाएगा। दूसरी ओर, BMW G 310 GS एडवेंचर मोटरसाइकिल 3.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है।

स्पेसिफिकेशन

KTM 390 Adventure मोटरसाइकिल का अपडेटेड वर्जन उसी 373.2 सीसी सिंगल-सिलेंडर और लिक्विड-कूल्ड इंजन द्वारा संचालित होता है, जो आउटगोइंग मॉडल में काम करता है। ये पावरप्लांट 9,000 आरपीएम पर 43 बीएचपी की अधिकतम पावर और 7,500 आरपीएम पर 37 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट देता है। ये इंजन 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, जिसमें क्विक-शिफ्टर और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच शामिल है।

BMW G 310 GS एडवेंचर मोटरसाइकिल 313 सीसी सिंगल-सिलेंडर और वॉटर-कूल्ड इंजन द्वारा संचालित होती है, जो 9,250 आरपीएम पर 34 बीएचपी की अधिकतम पावर और 7,500 आरपीएम पर 28 एनएम का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करती है। इस इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

फीचर से लैस हैं ये अफोर्डेबल फैमिली कारें, आपके बजट में भी बैठेंगी फिट

***budget family cars with air purifier Hyundai Exter** के टॉप मॉडल यानी **SX** मॉडल में कंपनी एयर प्यूरीफार फीचर ऑफर करती है। जिसकी शुरुआती कीमत 8 लाख 64 हजार रुपये है। एक्सटर पर पांच वेरिएंट ऑफर होंगे लाइन-अप एंट्री लेवल **EX S SX SX(O)** और टॉप-स्पेक **SX(O)** के साथ शुरू होगा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इसके सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड के तौर पर होंगे।*

purifier Hyundai Exter के टॉप मॉडल यानी SX मॉडल में कंपनी एयर प्यूरीफार फीचर ऑफर करती है। जिसकी शुरुआती कीमत 8 लाख 64 हजार रुपये है। एक्सटर पर पांच वेरिएंट ऑफर होंगे लाइन-अप एंट्री लेवल EX S SX SX(O) और टॉप-स्पेक SX(O) के साथ शुरू होगा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इसके सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड के तौर पर होंगे।

नई दिल्ली। इस समय दिल्ली-एनसीआर में काफी पॉल्यूशन है। जिसके चलते लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ऐसे माहौल में प्रत्येक गाड़ियों में एयर प्यूरिफायर फीचर का होना जरूरत बनती जा रही है। अगर आप अपने फैमिली के लिए नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके गाड़ी में एयर प्यूरिफिकेशन की सुविधा हो तो आप सही जगह पर है।

Renault Kiger

मैग्नेट के सामान्य दिखने वाली रेनॉल्ट किगर को 8.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत वाले रेंज-टॉपिंग आरएक्सजेड ट्रिम पर ऑप्शनल प्लस पैक के साथ एक एयर प्यूरीफायर भी मिलता है।

Nissan Magnite

अगर आप निसान मैग्नाइट खरीदते हैं तो इसमें आपको 38 हजार रुपये का टेक पैक लेना पड़ेगा, जिसमें आपको एयर प्यूरिफायर फीचर्स मिल जाएगा, निसान मैग्नाइट की शुरुआती कीमत 6 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। मैग्नाइट में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। ये पॉवरट्रेन 70 hp की शक्ति और 96 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है

Hyundai Exter

Hyundai Exter के टॉप मॉडल यानी SX मॉडल में कंपनी एयर प्यूरीफार फीचर ऑफर करती है। जिसकी शुरुआती कीमत 8 लाख 64 हजार रुपये है। एक्सटर पर पांच वेरिएंट ऑफर होंगे, लाइन-अप एंट्री लेवल EX, S, SX, SX(O) और टॉप-स्पेक SX(O) के साथ शुरू होगा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इसके सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड के तौर पर होंगे।

Hyundai Exter फीचर

कंपनी एक्सटर को फर्स्ट-इन-सेगमेंट सनरूफ, 8-इंच फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार तकनीक, वायरलेस चार्जर, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, सेमी-डिजिटल क्लस्टर और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स के साथ पेश कर सकती है।

इस दिवाली घर लाएं 10 लाख से सस्ती ये 5-स्टार SUVs, सेफ्टी के साथ मिलेगा फीचर्स और परफॉरमेंस का कॉम्बो

Mahindra XUV300 को Global NCAP में 5-स्टार रेटिंग दी गई है। XUV300 ने अडल्ट सुरक्षा के लिए 17 में से 16.42 और चाइल्ड सिक्योरिटी के लिए 49 में से 41.66 नंबर स्कोर किए हैं। ata Nexon को भी Global NCAP में 5-स्टार रेटिंग दी गई है। 2023 Tata Nexon ने अडल्ट सुरक्षा के लिए 17 में से 16.06 और चाइल्ड सिक्योरिटी के लिए 49 में से 25.00 नंबर स्कोर किए।

नई दिल्ली। अगर आप इस त्योहारी सीजन एक नई एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये 5-स्टार रेटिंग वाली सेफ कार हो, तो अपने इस लेख में हम आपके लिए ऐसी ही दो SUVs लेकर आए हैं। इन पांच सितारा एसयूवी को आप 10 लाख से कम दाम में खरीद सकते हैं। आइए, इन दोनों के बारे में जान लेत हैं।

Mahindra XUV300

Mahindra XUV300 को Global NCAP में 5-स्टार रेटिंग दी गई है। XUV300 ने अडल्ट सुरक्षा के लिए 17 में से 16.42 और चाइल्ड सिक्योरिटी के लिए 49 में से 41.66 नंबर स्कोर किए हैं। आपको बता दें कि इसकी एक्स शोरूम कीमत 8.42 लाख रुपये से शुरू होकर 12.38 लाख रुपये तक जाती है। महिंद्रा की ये कार स्टाइल या प्रदर्शन से समझौता किए बिना बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है।

Tata Nexon

Tata Nexon को भी Global NCAP में 5-स्टार रेटिंग दी गई है। 2023 Tata Nexon ने अडल्ट सुरक्षा के लिए 17 में से 16.06 और चाइल्ड सिक्योरिटी के लिए 49 में से 25.00 नंबर स्कोर किए हैं। टाटा नेक्सन सामर्थ्य और सुरक्षा का एक बेहतरीन मिश्रण है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 7.54 लाख रुपये से लेकर 13.80 लाख रुपये तक है।

इसके अलावा महिंद्रा की ओर से XUV300 पर बेहतरीन डिस्काउंट दिया जा रहा है। एसयूवी के टॉप-एंड W8 वेरिएंट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें 95 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट शामिल है। इसके अलावा W6 वेरिएंट को 80 हजार रुपये की छूट पर खरीद सकता है, जिसमें 25,000 रुपये की एक्सेसरीज शामिल हैं। इस तरह आप नई एक्सयूवी300 खरीदने पर बेहतरीन डिस्काउंट पा सकते हैं।

चुनाव दर चुनाव बढ़ती जा रही है बागियों की संख्या

ललित गर्ग

टिकट बंटवारे में आलाकमान बहुत बारीकी से निर्णय लेता है, महीनों तक भीतर-ही-भीतर योग्य उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में पार्टी की चलने वाली गंभीर विश्लेषण-जांच एवं अनुसंधान की गहरी भूमिका होती है, अब कोई धमक, सेवा एवं पैसा काम नहीं आता।

पांच राज्यों के विधानसभा से पहले अनेक राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओं के बीच बड़ी उठापटक, खींचतान एवं चरित्रगत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस ही आमने-सामने की स्थिति में हैं, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर इन दोनों ही दलों में दोनों ही राज्यों में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। दोनों ही दलों में अपने आपको पार्टी का सर्वेसर्वा मानने वाले नेताओं की इस बार टिकट बंटवारे में दाल नहीं गली और वे अपने चेहतों को टिकट देने में नाकाम साबित हुए, जिससे दोनों ही दलों में भारी असंतोष एवं विद्रोह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के शीर्ष नेताओं को भी टिकट न मिलने से बागी एवं बगावती स्वर उभर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अब चुनाव का टिकट पाना या उसका कटना ही नेताओं के जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है? क्या पार्टी के प्रति बफादारी का गुब्बारा एक टिकट न मिलने की सूई से ही हवा शून्य हो गया है? एक प्रश्न और है कि टिकट क्या किन्हीं नेताओं की बपौती है, फिर बाकी कार्यकर्ताओं का क्या वजूद है जो सालों से पार्टी के लिये जी-जान लगाये होते हैं? क्या राजनीति अब सबसे ज्यादा लाभ और रौब का धंधा बन चुकी है? लोकतंत्र में जब मूल्य एवं सिद्धान्त कमजोर हो जाते हैं और सिर्फ निजी हैसियत को ऊंचा करना ही महत्वपूर्ण हो जाता है वह लोकतंत्र निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है। अफसोस, कि जिस जन की सेवा के लिए चुनाव टिकट रूपी एंट्री पास तैयार किया गया है, वह 'जन' पहले भी हतप्रभ था, आज भी है और शायद आगे भी रहेगा। क्योंकि आम मतदाता तो पहले भी ठगा जाता था, गुमराह किया जाता था। आज भी उसके साथ यही हो रहा है? टिकट की दौड़ के लिये सक्रिय होने एवं पांच साल में केवल चुनाव के समय नजर आने वाले उम्मीदवारों को दोनों पार्टियों ने टिकट न देकर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजनीति में ऐसे ही साहसिक एवं अभिनव प्रयोग की अपेक्षा है, ताकि राजनीति में प्रतिनिधित्व की पात्रता किन्हीं सीमित हाथों से बाहर आये एवं नये चेहरों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिले।

राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन के आखिरी दिन अनेक चेहरों को निराशा हाथ लगी है। भाजपा की आखिरी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन इस लिस्ट में केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया है। भाजपा ने इस बार वसुंधरा राजे के कई समर्थकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी प्रमुख हैं और दोनों नेता ऐसे हैं जो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके साथ ही पूर्व मंत्री एवं राजे के खास यूनुस खान का भी टिकट काट दिया गया है। राजपाल सिंह शेखावत और राव राजेन्द्र का टिकट भी पार्टी ने काट दिया है।

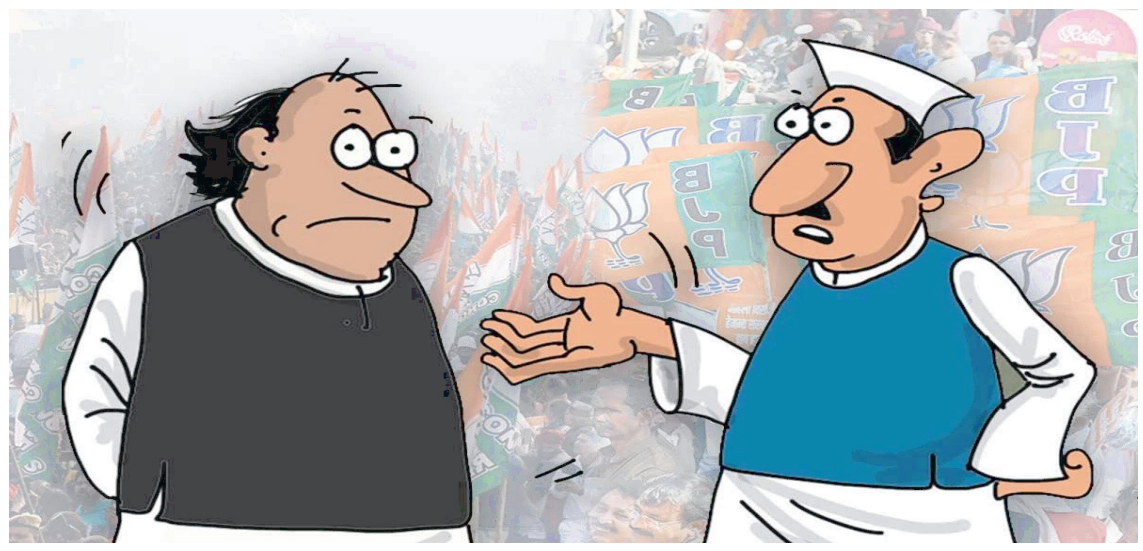

कांग्रेस में भी ऐसे अनेक महत्वपूर्ण चेहरों को निराशा हाथ लगी है। टिकट न मिलने से पार्टी के इन वफादार सैनिकों के स्वरों में भी बगावत देखने को मिल रही है। निश्चित ही दोनों ही दलों में टिकट बंटवारे में आजमाये इन नये प्रयोगों का व्यापक असर देखने को मिलेगा। राजस्थान के अनेक राजनीतिक विश्लेषकों से चर्चा से यह तथ्य भी सामने आया है कि दलों में हो रहे इन बदलावों का नकारात्मक ही नहीं, सकारात्मक परिणाम भी सामने आयेगा।

चुनाव के समय राजनीतिक दलों में टिकट वितरण को लेकर असंतोष होना स्वाभाविक है। जो राजनीतिक कार्यकर्ता वर्षों मेहनत करे और टिकट वितरण के समय उसे दरकिनार कर दूसरे या किसी आयातित व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए तो राजनीति में निष्ठा और समर्पण का पैमाना अपने आप ध्वस्त होने लगता है। वैसे भी हर पार्टी में एक सीट पर टिकट के एक से अधिक आकांक्षी होते हैं। दलों की संवैधानिक मर्यादा एवं सीमाएं हैं कि वे चुनाव में किसी एक को ही टिकट दे सकती हैं। ऐसे में बाकी को या तो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का समर्थन करना होगा या फिर दूसरे किसी दल से टिकट लेकर अथवा निर्दलीय चुनाव में खड़ा होना होगा। टिकट न मिलने वालों को अपनी नाराजगी प्रकट करने का अधिकार है, वे चाहें तो पार्टी हाई कमान और टिकट वितरणकर्ताओं के सामने खुलकर अपनी नाराजगी का प्रदर्शन कर मन को हल्का करें या अनैतिक विकल्प के तौर पर पार्टी में रहकर ही भितरघात कर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हरवाकर अपनी उपेक्षा का बदला लें और अगले चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का खाता खुला रखें। राजस्थान में ऐसे ही सीन बन रहे हैं, अब विरोध के प्राचीन तरीकों जैसे कि नारेबाजी, धरना प्रदर्शन से मीलों आगे जाकर शीर्ष नेताओं के घरों के सामने आत्मदाह करने, पार्टी दफ्तरों पर हमले, नेताओं के कपड़े फाड़ने, हाथापाई, सामूहिक इस्तीफे और टिकट कटने के बाद मातमी अंदाज में जार-जार आंसू बहाने की स्थितियां समाप्त हो गयी हैं। अब तो पार्टियों में विरोध प्रदर्शन का सबसे सशक्त हथियार निर्दलीय चुनाव लड़ना या भितरघात करना ही देखने को मिल रहा है। मानो सभी दलों में अनुशासनहीनता और अराजकता की एक अघोषित स्पर्धा चल रही हो, जिसमें हर असंतुष्ट अपने गिरोह के साथ दूसरे को पीछे छोड़ने की दबंगई में लगा है। ऐसा नहीं है कि आला नेताओं को कार्यकर्ताओं के इस तरह उग्र अथवा बागी होने का अंदाजा न हो। लेकिन पार्टियां चुनाव का टिकट बांटती हैं तो टिकट देने और टिकट काटने के उसके अपने पैमाने होते हैं। उनकी अपनी सीमाएं भी होती हैं।

टिकट बंटवारे में आलाकमान बहुत बारीकी से निर्णय लेता है, महीनों तक भीतर-ही-भीतर योग्य उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में पार्टी की चलने वाली गंभीर विश्लेषण-जांच एवं अनुसंधान की गहरी भूमिका होती है, अब कोई धमक, सेवा एवं पैसा काम नहीं आता। यहां तक बड़े नेताओं के निजी संबंध भी अब कारगर नहीं रहे। एक-एक पात्र उम्मीदवार पर हर कोण से गंभीर रिपोर्ट तैयार होती है और वही टिकट बंटवारे का माध्यम बनती है। इसलिये अब बगावत एवं विद्रोह के उतने नुकसान भी नहीं देखने को मिलते, जितने पहले हुआ करते थे। पार्टी हित में शीर्ष नेतृत्व ऐसे बगावती स्वरों को शांत करने की पूरी कोशिश करता है। राजस्थान में अनेक टिकट वंचित उम्मीदवार छोटे दलों के टिकट पर या निर्दलयी चुनाव मैदान में उतरने का एलान कर चुके हैं। हालांकि, नाराजों को बिठाने और चुप कराने के लिए दोनों दलों में बड़े नेता साम-दाम-दंड-भेद सभी तरीके अपनाने में लगे हैं। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता यह बखूबी जानता है कि बड़े नेताओं द्वारा उससे किए वादे भी ज्यादातर चुनावी वादों की तरह खोखले अथवा आधे-अधूरे होते हैं। साथ में यह भी सच है कि बड़े दलों में अब वो ऋषि एवं कद्दावर राजनेताओं का अभाव है, जिनके इशारों पर आक्रोश एवं विद्रोह शांत हो जाते थे। ऐसे दिग्गज नेताओं का नैतिक प्रभाव खत्म होने के बाद आजकल कार्यकर्ताओं को मनाने का फार्मूला मोटे तौर पर अगले चुनाव में टिकट के वादे, सत्ता में आने पर किसी पद की रेवड़ी, या फिर बात-बेबात उसकी पीठ थपथपाने, मंच से तारीफ के दो शब्द कहकर भावनात्मक शोषण करने या फिर धन के रूप में ही देखने को मिल रहा है।

लेकिन पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा सवाल तो राजनीति में बुनियादी नैतिकता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का है? लोकतंत्र में चुनाव टिकट की आकांक्षा रखना स्वाभाविक है, लेकिन उसे जीने-मरने का सवाल बना देना या उसे विसंगतियों एवं विडम्बनाओं का शिखर बना देना क्या संदेश देता है? दरअसल राजनीतिक व्यवस्था मूलतः लोकतंत्र को चलाने और इस तंत्र के असल मालिक लोक के जीवन को सुचारू और समृद्ध बनाने के लिए है, लोकतांत्रिक माफिया बनने के लिए तो कत्तई नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के अमृत काल में यह कड़वा सच है कि राजनीति अब अधिकांश लोगों के लिए शुद्ध रूप से चौतरफा लाभ का धंधा है। इसीलिए वो इसे छोड़ना तो दूर इसे पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखना चाहते हैं ताकि पावर, पैसा और प्रतिष्ठा की गंगोत्री सूख न सके।

संपादक की कलम से

विकास का अनूठा व्याकरण

'चलो कहीं भरपूर विकास दिखाया जाए, सियासी मिट्टी पर सीमेंट उगाया जाए।' कुछ इसी तरह के उदाहरणों का मिट्टी परीक्षण होता रहा है और वर्तमान सरकार ने भी निरीक्षण-परीक्षण की जिरह पैदा करते हुए, हिमाचल में प्रगति का मुआयना शुरू किया है। संस्थानों की डिनोटिफिकेशन के बाद यह तो साबित हो रहा है कि चुनावी जुबान ने सत्तापक्ष की दिलदारी के नक्शे पर ऐसा नुकसान कर दिया जो प्रदेश के बूते से बाहर है। इसी परिप्रेक्ष्य में तीन अटल आदर्श विद्यालयों की रिपोर्ट भी निराशाजनक स्थिति पैदा कर रही है। जयराम सरकार ने शिक्षा के आदर्शों को सिर पर चढ़ा कर अटल आदर्श विद्यालय का जो ढोल पीटा था, उसकी असलियत अब सामने आ रही है। पहले चरण में 13 अटल विद्यालयों में से मात्र तीन ही जमीन पर उतर पाए और अब पता यह चल रहा है कि इनके ऊपर सौ करोड़ खर्च करके भी छात्र नहीं मिल रहे। यह अनोखे विकास का व्याकरण जिसे राजनीति सिद्ध करना चाहती है। विश£ेषण यह भी बताता है कि जब ऐसी परियोजनाएं बनती हैं, तो उनकी भूमिका से कहीं अधिक पैरवी से क्षेत्रवाद को संतुष्ट किया जाता है। इन विद्यालयों ने भी मंडी के नाचन और धर्मपुर में अपना अड्डा जमाया, जबकि सबसे बड़े कांगड़ा तथा उसके उपरांत शिमला जिला को इसकी फेहरिस्त में कोई दौर नहीं मिला। ऐसी इमारतों के शर्मिंदा होने पर भी हमें कोई नसीहत नहीं मिलती। कुछ साल पहले धर्मशाला-शिमला हाई-वे पर बड़ी महत्त्वाकांक्षा से पर्यटन कक्ष खोला गया, लेकिन इसका आगाज ही इसका अंत बना। इसी तरह नूरपुर में दो बार पर्यटन इकाइयां खोली गईं, लेकिन जनता को सिर्फ एक नालायकी मिली। हमने प्रदेश में तैंतीस स्नातकोत्तर कालेज बना दिए, लेकिन पाठ्यक्रम तो हर विश्वविद्यालय परिसर में हार रहा। सरकार के बेहतरीन विद्यालय अब केवल एक बड़ी इमारत हैं, जो हर मेरिट और परीक्षा परिणाम में निजी स्कूलों से हार रहे हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार ने भी अटल आदर्श विद्यालय के सामने राजीव डे बोर्डिंग स्कूल का पंजा लड़ा दिया है। एक विफल प्रयास की दो समानांतर धाराएं बता रही हैं कि कहीं गड़बड़ी व्यवस्थागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की हर इमारत को न तो प्रतिस्पर्धा के मायने मालूम हैं और न ही हारने का खौफ है, नतीजतन हिमाचल ने क्षमता से अधिक स्कूल, कालेज, दफ्तर तथा मेडिकल संस्थान खोलकर गुणवत्ता के हिसाब से कुछ भी हासिल नहीं किया। हर बार बीमार होने पर विभिन्न सरकारों के मुख्यमंत्री एम्स दिल्ली रवाना होते रहे, लेकिन हिमाचल के छह सरकारी एक निजी तथा बिलासपुर एम्स-ऊना पीजीआई सेटेलाइट सेंटर खोलकर भी हमारी स्वास्थय सेवाएं बाहरी प्रदेशों पर आश्रित हैं। अभिभावक तलाश में हैं कि उनके बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा कहां मिलेगी, मरीज पीजीआई चंडीगढ़ या लुधियाना के अस्पताल तक पहुंचना चाहते हैं। अगर निकम्मे साबित हो रहे स्कूल-कालेजों की इमारतों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाया जाए, तो भी शिक्षा का भला हो सकता है, वरना जो अटल आदर्श विद्यालय बन न कर सका, वह राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बन कर क्या कर पाएगा। हिमाचल में अब भी कई स्कूल-कालेजों, दफ्तरों व चिकित्सा संस्थानों को बंद करने की जरूरत है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की नाक बचाई जा सके, वरना धीरे-धीरे लोगों की हर सेवा के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। प्रदेश सरकार प्रमुख शहरों के सरकारी स्कूलों को या तो सीबीएसई या आईसीएसई पाठ्यक्रम के तहत चलाए तो भी अंतर आएगा। दूसरी ओर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का करियर के हिसाब से कुछ स्कूलों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर दसवीं परीक्षा के आधार पर शिक्षा बोर्ड टेलेंट सर्च करके पांच हजार बच्चों को मेरिट के आधार पर बोर्डिंग स्कूल उपलब्ध कराए, तो प्रदेश में एक दर्जन करियर विद्यालय बन सकते हैं। जमा एक व जमा दो कक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड बड़े शहरी स्कूलों का हुलिया व मांग बदल सकता है। इतना ही नहीं ऐसी ही मेरिट के आधार पर ये स्कूल छात्रों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं तथा राष्ट्रीय स्तर के रोजगार के अलावा विभिन्न खेलों के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं।

राय

कब तक चलेगा युद्ध

इजरायल-हमास युद्ध को एक महीना बीत चुका है। हमास आतंकी गुट के कई ठिकाने, कमांड सेंटर 'मलबा' किए जा चुके हैं। कई कमांडरों को ढेर करने के दावे इजरायली सेना कर रही है। हमास की भूमिगत सुरंगों को भी 'मिट्टी' किया जा रहा है। हालांकि इस जमीनी लड़ाई में इजरायल के भी 30 से ज्यादा सैनिक 'शहीद' हो चुके हैं। हजारों टन बारूद की बमबारी की जा चुकी है। मिसाइल, रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस अवधि में 10,000 से अधिक मासूम लोग मारे जा चुके हैं। उनमें आधे तो बच्चे होंगे! घायलों का आंकड़ा अनिश्चित है, क्योंकि उनके इलाज करने वाले अस्पताल या तो ध्वस्त किए जा चुके हैं अथवा उनमें दवाइयां, इलाज की सामग्रियां उपलब्ध नहीं हैं। सब कुछ तबाह होता जा रहा है, मानो मानवीय जीवन की कोई कीमत ही नहीं है! हमास के आतंकियों ने 7 अक्तूबर को इजरायल पर अचानक बेरहम हमला किया था। आंकड़े बताते हैं कि उसमें करीब 1500 लोगों का कत्लेआम किया गया। आतंकियों ने 200 से अधिक बेकसूर लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें या तो हमास के कब्जे में होंगे अथवा मार दिए गए होंगे! कोई निश्चित सूचना नहीं है। आक्रमण न केवल जारी है, बल्कि हमास के समर्थन में लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूती आतंकी संगठन भी युद्ध में उतर आए हैं। वे इजरायल पर हवाई हमले भी कर रहे हैं। अब हमास परमाणु बम की बात भी करने लगा है। आतंकियों के पास परमाणु बम कहां से आए? ईरान पर संदेह होता है, क्योंकि वह युद्ध की शुरुआत से ही फिलिस्तीन की आड़ में हमास का समर्थन करता रहा है। कल्पना करें कि यदि किसी भी इलाके पर परमाणु बम गिराया गया, विस्फोट सफल रहा, तो विध्वंस कितना होगा? हिरोशिमा और नागासाकी को अभी भूलना नहीं चाहिए। आतंकी किसी अंतरराष्ट्रीय नियम-कानून से तो बंधे नहीं हैं। बेशक इजरायल को अपने नागरिकों की रक्षा करने और उन पर किए गए हमले का पलटवार करने का अधिकार है, लेकिन वैश्विक चिंता और सरोकार यह भी है कि आखिर यह युद्ध कब तक चलेगा? क्या युद्ध अनिश्चितकाल तक जारी रह सकता है? इजरायल ने अपना लक्ष्य तय किया है कि वह हमास का अस्तित्व समाप्त करके ही दम लेगा, लेकिन एक माह के युद्ध के बावजूद हमास अब भी जिंदा है और इजरायल के शहरों पर मिसाइल, रॉकेट दाग रहा है। बेशक इजरायल की सेना और हथियार उच्च तकनीक के हैं। उसकी वायु सुरक्षा प्रणाली भी काफी हद तक अभेद्य है, लेकिन यह युद्ध और खासकर गाजा पट्टी मानवीय संकट का 'कुरुक्षेत्र' बन गया है और अभी युद्धविराम के कोई आसार नहीं हैं। हालांकि अमरीका, भारत और कुछ यूरोपीय देश, अपने मित्र-देश इजरायल को, समझा रहे हैं कि मानवीय हताहतों की संख्या कम की जाए। इजरायल ठोस खुफिया सूचनाओं के आधार पर ही हमले करे, ताकि हमास को ही सीधे निशाना बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में भी युद्धविराम के पक्ष में प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन इजरायल इस बार हमास को बिल्कुल मटियामेट कर देना चाहता है। लेकिन हजारों मासूमों की हत्या करके इजरायल को विरोधी देशों की घेराबंदी में सुरक्षित नहीं माना जा सकता, क्योंकि दुनिया यहूदी बनाम मुसलमान में बंट गई है। कोई भी मुस्लिम और अरब देश खुलेआम हमास को 'आतंकी संगठन' मानने को तैयार नहीं है। अधिकतर ने 7 अक्तूबर के हमले की बर्बरता की भत्र्सना भी नहीं की है। उनके लिए इजरायल ही 'खलनायक' और 'हत्यारा' है। युद्ध से अलग घरेलू स्तर पर विश्लेषण करें, तो इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज भी राजनीतिक तौर पर अलोकप्रिय और अस्वीकार्य नेता हैं।

शास्त्री उपाधिधारक ही टीजीटी के लिए पात्र हों

उपरोक्त सभी (शास्त्री एवं बीए संस्कृत) उपाधि के बीच अंतर प्रदर्शित करने वाले तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शास्त्री पद हेतु केवल शास्त्री उपाधि प्राप्त छात्रों को ही योग्य माना जाना तर्कसंगत है'

हिमाचल में शास्त्री अध्यापकों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम काफी समय से विवाद एवं चर्चा का विषय रहे हैं। राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद तथा संस्कृत विकास हेतु प्रतिबद्ध अन्य संगठन संस्कृत शिक्षकों के लिए अन्य शिक्षकवर्ग के समान विसंगतिहीन भर्ती एवं पदोन्नति नियम हेतु सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखते आए हैं, किन्तु अनेक दशकों के बीत जाने के बावजूद शास्त्री अध्यापकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति की उचित नियमों की व्यवस्था नहीं हो पाई। इस विषय में सर्वप्रथम यह जानना प्रासंगिक होगा कि विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाने वाली उपाधि 'शास्त्री' क्या है, क्योंकि शास्त्री डिग्री के विषय में जनसामान्य में अनेक मिथ हैं, जिसका निराकरण अत्यावश्यक है। वस्तुतः शास्त्री उपाधि एक पंचवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (स्नातक डिग्री) है, जिसे यूजीसी से संबद्धता प्राप्त किसी संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा संस्कृत महाविद्यालय से दसवीं कक्षा के पश्चात 5 वर्ष तथा प्लस टू के बाद 3 वर्षों में प्राप्त की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली शास्त्री की डिग्री बी. कॉम. और बीएससी (मेडिकल, नॉन मेडिकल) की तरह एक विशिष्ट डिग्री है जिसमें छात्र वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि शास्त्रीय विषयों को पढ़ता है। जिस प्रकार बी. कॉम. में अकाउंटेंसी, बिजनेसस्टडी, गणित आदि तथा बीएससी में गणित, भौतिकी, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान आदि विषयों को पढ़ता है। भारतवर्ष में संस्कृत का पठन-पाठन दो तरह से होता है। पारम्परिक संस्कृत विषय (शास्त्रों का अध्ययन) तथा आधुनिक संस्कृत विषय (सामान्य संस्कृत का अध्ययन)।

संस्कृत विश्वविद्यालयों, संस्कृत महाविद्यालयों तथा गुरुकुलों में पारम्परिक संस्कृत विषय का अध्ययन होता है, जिसमें मुख्य रूप से शुक्लयजुर्वेद, कृष्णयजुर्वेद, फलितज्योतिष, सिद्धांतज्योतिष, प्राचीनव्याकरण, नव्यव्याकरण, नव्यन्याय, धर्मशास्त्र, साहित्यशास्त्र आदि शास्त्रीय विषय सम्मिलित हैं। इन संस्थानों से शास्त्री (ग्रेजुएशन) आचार्य (मास्टर्स), शिक्षा शास्त्री (बी. एड.) आदि डिग्रियां होती है। संस्कृत विश्वविद्यालयों से भिन्न केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों तथा डिग्री महाविद्यालयों में जहां संस्कृत विषय होता है, वहां बी. ए. में सामान्य संस्कृत विषय पढ़ाया जाता है। विशेष रूप से ज्योतिष, वेद, कर्मकांड आदि के अध्यापन की व्यवस्था नहीं है। यहां से केवल छात्र बी. ए. (संस्कृत) का अध्ययन करते हैं। हाल ही में टीजीटी संस्कृत पद के लिए राज्य सरकार ने एनसीटीई के नियम लागू किए हैं जिनमें शास्त्री पद के लिए शास्त्री के साथ बी. एड. अनिवार्य की गई है। बी. एड. की अनिवार्यता शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ठीक भी है, किन्तु इसमें बी. ए. (संस्कृत) को भी योग्य माना गया है। शास्त्री उपाधिधारी इस पर पुनर्विचार करने की माँग उठा रहे हैं। पाठ्यक्रम एवं विषयवस्तुज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए तो शास्त्री उपाधिधारी और बी. ए. संस्कृत उपाधिधारी में पर्याप्त अन्तर है। पहला अन्तर यह है कि संस्कृत महाविद्यालयों में होने वाली प्राकशास्त्री (द्विवर्षीय) में व्याकरण, नाटक, अनुवाद रचना तथा दर्शन के (8 पत्र) तथा शास्त्री डिग्री (त्रिवर्षीय) में शास्त्री विद्यार्थी लगभग 5 पारम्परिक संस्कृत विषय (वेद, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन, साहित्य) के 24 पत्र पढ़ता है। इस प्रकार कुल (24 प्लस 8) 32 पत्र संस्कृत के पढ़ता है, जबकि डिग्री महाविद्यालयों में बी. ए. में सामान्य संस्कृत (साहित्य-व्याकरण) के 1-2 विषय के मात्र 6 पत्र पढ़ता है। दोनों की तुलना सम्भव नहीं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे बीएससी और बीए (आट्र्स विद मैथ्स) की तुलना करना। दूसरा अन्तर यह है कि पारम्परिक संस्कृत संस्थानों में शास्त्र का पठन-पाठन संस्कृत माध्यम में होता है और परीक्षा भी संस्कृत में लिखनी होती है। जबकि बी. ए. में संस्कृत विषय को हिन्दी में लिखने की छूट है। वहां संस्कृत माध्यम में लिखने की बाध्यता नहीं। संस्कृत शास्त्रों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शास्त्र संस्कृत में लिखे गए हैं।

शास्त्रों के जटिल एवं दुरुह सिद्धांतों को भाष्य तथा टीकाग्रंथों से समझा जा सकता है। ये सभी भाष्य एवं टीका ग्रन्थ संस्कृत भाषा में रचित हैं। शास्त्रीय विषय के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन संस्कृत में हो। इन ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन (सूत्र-भाष्य-टीका-व्याख्या-प्रकरणग्रन्थ) की हजारों वर्षों की अक्षुण्ण परम्परा संस्कृत भाषा में रही है, जिसका समाश्रयण अत्यन्त आवश्यक है। तीसरा अन्तर यह है कि पारम्परिक संस्कृत के बहुत से विषयों की अध्ययन की व्यवस्था डिग्री महाविद्यालयों में नहीं। फलितज्योतिष तथा सिद्धान्त ज्योतिष के महत्वपूर्ण ग्रन्थ गोलपरिभाषा, लघुपाराशरी, सूर्यसिद्धान्त, मुहूर्तचिंतामणि जैसे मुहूर्त एवं कालज्ञापक शास्त्रों के पठन की व्यवस्था केवल संस्कृत महाविद्यालयों में है। इन विषयों के ज्ञान के बिना यज्ञ, पर्वोत्सव, संस्कारों का समुचित ज्ञान संभव नहीं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रन्थ जैसे लघुसिद्धांतकौमुदी, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, वैदिक कर्मकांड, रुद्राष्टाध्यायी, साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश इत्यादि को पंक्तिशः पढ़ाने की व्यवस्था केवल संस्कृत महाविद्यालयों में है, डिग्री महाविद्यालयों में ऐसी व्यवस्था नहीं। अतः दोनों उपाधियों में पर्याप्त अन्तर है। यह अन्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) पाठ्यक्रम में विहित विषयविभाजन से भी स्पष्ट है।

जहां पारम्परिक संस्कृत और आधुनिक संस्कृत को अलग-अलग कोड की व्यवस्था दी गई है। दोनों विषयों में समानता होती तो यूजीसी को अपने पाठ्यक्रम में पारम्परिक संस्कृत के लिए 73 कोड तथा आधुनिक संस्कृत के लिए 25 कोड जैसी व्यवस्था न करनी पड़ती। उपरोक्त सभी (शास्त्री एवं बीए संस्कृत) उपाधि के बीच अन्तर प्रदर्शित करने वाले तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शास्त्री पद हेतु केवल शास्त्री उपाधिप्राप्त छात्रों को ही योग्य माना जाना तर्कसंगत है। यदि बीए (संस्कृत) छात्रों को शास्त्री पद के लिए योग्य माना जाएगा तो 5 वर्षों में शास्त्रों का गहन अध्ययन करने वाले छात्रों के साथ अन्याय होगा। जब शास्त्री पद के लिए हिन्दी माध्यम से मात्र छह-सात पत्र पढक़र योग्यता प्राप्त होगी तो संस्कृत माध्यम से 32 पत्र पढने के लिए संस्कृत महाविद्यालय में कौन प्रवेश लेगा?

छिलकों की छाबड़ी : विश्व गुरु की कानी आंख

मेरे मन में सवाल कौंध रहा है कि क्या इस बार भी विश्व गुरू साल 2019 की तरह 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों से पूर्व केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाएंगे। पर मैं इतना मंद बुद्धि हूँ कि गूगल बाबा पर हर तरह की जानकारी चिपकी होने के बावजूद इस घटना के चार साल गुजऱने के बाद भी अभी तक यह पता नहीं लगा पाया हूं कि क्या किसी संत के प्राकृतिक गुफा में ध्यान लगाने से वह ध्यान गुफा बनती है या किसी प्रधानमंत्री के लिए लाखों रुपये ख़र्च करने के बाद बनाई गई विशेष सरकारी गुफा में उसके ध्यान लगाने के बाद प्रचार के माध्यम से वह ध्यान गुफा में बदल जाती है। पर ज़माना प्रचार का है। एक ख़बर जो समाचार की बजाय विज्ञापन प्रतीत हो रही है, को पढने पर पाता हूं कि इस घोर कलियुग में भी लोग उस गुफा में ध्यान लगाने के लिए अग्रिम बुकिंग करवा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने चार बरस पहले कनुआ ध्यान लगाया था। पता नहीं कमाल इस कृत्रिम ध्यान गुफा का है या चारधाम यात्रा का, पर श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शनों के लिए पंजीकरण के अलावा इस ध्यान गुफा में काफी रुचि ले रहे हैं।

प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक ध्यान की ऐतिहासिक घटना के बाद से इस ध्यान गुफा की बंपर बुकिंग चालू है। पर मेरे दिल में खयाल आ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री का मन इस गुफा में दोबारा फोटो शूट करवाने के लिए मचल पड़े तो क्या श्रद्धालुओं की बुकिंग रद्द हो जाएगी या प्रधानमंत्री के लिए किसी नई फाईव स्टार गुफा का निर्माण करवाया जाएगा। चाहे जो भी हो, पर कैमरे के सामने उनके एक नेत्रीय ध्यान के बाद यह गुफा भी पिछली गुफा की तरह ध्यान गुफा के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगी। इस बात की भी पूरी संभावना है कि मोदिया चैनल का कोई ख़बरघसीट घोषित कर दे कि इस गुफा में आज भी महावतार बाबा तप में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री द्वारा देश को विश्व गुरू बनाने की ख़ुशी में महावतार बाबा उनसे विशेष भेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि यह ख़बरघसीट प्रधानमंत्री की उस विशेष भेंट का अपने चैनल से यह कहते हुए लाईव प्रसारण करे कि चूंकि महावतार बाबा केवल अपने विशेष शिष्यों को ही दर्शन देते हैं, अतः इस विशेष प्रसारण में केवल प्रधानमंत्री ही फ्रेम में एकालाप करते हुए नजऱ आएंगे।

हालांकि प्रधानमंत्री के लिए एकालाप कोई नई बात नहीं। मन की बात या उनके भाषण एकालाप के जीवन्त उदाहरण हैं। यह भी संभव है कि ख़बरघसीट बाक़ायदा सिद्ध कर दे कि अमेरिका जाने से पहले विवेकानंद इस गुफा में समाधिस्थ रहे थे। मेरी नजऱ प्रधानमंत्री के उस फोटो से बिल्कुल नहीं हट रही, जिसमें वह चश्मा पहन कर ध्यान कर रहे हैं, वह भी एक आँख कानी रखते हुए। बचपन में बच्चे चोर-सिपाही या लुका-छिपी खेलते हुए अक्सर दोनों आँखों को बंद रखने का अभिनय करते हुए कानी आँख से अपने साथियों को देखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री ने यह देखने के लिए एक आँख को कानी रखी हो कि उनके ईष्ट कहाँ छिपे हैं। पर आज़ादी के बहते हुए अमृत के कर्तव्य काल में देश में 'मेरी बाईं आँख कानी, तेरी दाईं आँख कानी' कहावत इस तरह फलीभूत हो रही है कि जनता तो सब देख रही है पर सरकार, मोदिया जगत और अंधभक्तों को कुछ नहीं दिख रहा। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इनकी बची-खुची नजऱ भी खऱाब होती जा रही है। विसल ब्लोअर जेल भेजे जा रहे हैं और चोर प्रधानमंत्री के साथ मोरों को दाना खिला रहे हैं। मोदिया चैनल और अख़बार प्रशस्ति गायन कर रहे हैं और अंधभक्त तालियाँ बजा रहे हैं। ऐसे में मुझे दूसरी कहावत याद आ रही है 'कानी आँख मटर का बिया, वो भी आँख भवानी लिया।' शायद इसलिए परसाई जी ने प्रेमचंद जी के फटे जूतों को काना नहीं कहा होगा। कहते तो मेरी तरह द्वंद्व में रहते। लेकिन इसके बावजूद मुझे किसी बात की चिंता नहीं क्योंकि 'लक्कडियाँ बाँसे की, कानी आँख तमाशे की।'

धनतेरस से पहले आज लुढ़क गए सोने के भाव, जानिए आपके शहर में क्या है गोल्ड की कीमत

अगर आप सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मौजूदा समय में बाजार में सोने और चांदी की कीमत में कमी आई है। धनतेरस में सोना खरीदे की लूट मची होती है जिससे देश भर में सोने की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से सोने की कीमतों में भी उछाल देखने को मिलता है।

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में अगर आप सोना खरीदने का सोच रहे थे तो आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में आपके शहर में सोने और चांदी का क्या भाव है यह आपको पता होना चाहिए।

आज कितना सस्ता हुआ सोना?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार, वैश्विक बाजारों में कमजोर संकेत के कारण दिल्ली में सोने की कीमत 250 रुपये घटकर 61,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। पिछले कारोबार में सोना 61,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

वायदा कारोबार में सोना

आज वायदा कारोबार में सोने की कीमत 292 रुपये गिरकर 60,478 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 292 रुपये या 0.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60,478 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 13,539 लॉट का कारोबार हुआ।

क्या है आज चांदी की कीमत

सर्राफा बाजार में आज चांदी 650 रुपये टूटकर 74,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।वहीं वायदा कारोबार में आज चांदी 865 रुपये गिरकर 71,252 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 865 रुपये या 1.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 71,252 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया, जिसमें 19,828 लॉट का कारोबार हुआ।

अक्टूबर में सस्ती हुई वेज और नॉन वेज थाली
नवंबर में जेब होगी ढीली; जानें क्या है वजह

क्रिसिल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने यानी अक्टूबर में खाने की थाली की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ताजा आंकड़ों के मुताबिक घर पर तैयार की जाने वाली शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की थालियों की कीमतों में गिरावट आई है। इसकी वजह आलू टमाटर खाना पकाने का तेल दालें चिकन रसोई गैस आदि की कीमतों में गिरावट बताई जा रही है।

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी और रिसर्च फर्म क्रिसिल की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले महीने यानी अक्टूबर में भोजन की थाली की कीमतों में राहत देखी गई।

लेटेस्ट आंकड़ो के मुताबिक घर पर तैयार शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थालियों की कीमत में कमी देखी गई। इसका कारण आलू, टमाटर, खाद्य तेल, दाल, चिकन, रसोई गैस इत्यादि की कीमतों में गिरावट को बताया गया है।

कीमतों में कितनी आई कमी?

क्रिसिल के मुताबिक घर में पकाई गई शाकाहारी थाली की कीमत साल दर साल 5 प्रतिशत तक गिरी है। इसके अलावा मांसाहारी थाली की कीमत में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है।

क्या कहते हैं आंकड़े?

क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में आलू की कीमतों में सालाना आधार पर 21 प्रतिशत और टमाटर की कीमत में 38 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

नॉन-वेज थाली की बात करें तो चिकन की कीमत में सालाना आधार पर 5 से 7 प्रतिशत तक की कमी आई थी। इसके अलावा क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक रसोई गैस में आई कमी के कारण भी वेज और नॉन वेज थाली की कीमतें प्रभावित हुई है।

इस महीने बढ़ सकती है कीमत

रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने यानी नवंबर में थाली की कीमतों में इजाफा हो सकता है। क्रिसिल के मुताबिक अगर इस महीने प्याज की कीमत करीब 10 प्रतिशत तक बनी रहती है तो थाली की कीमत बढ़ सकती है।

शाकाहारी थाली की कुल लागत में 9 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली दालों की कीमत में साल-दर-साल 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

सितंबर में कितनी कम हुई थी कीमत?

सितंबर में शाकाहारी थाली की कीमत 17 प्रतिशत तक गिरी थी। कीमतों में कमी टमाटर के दाम घटने के कारण हुई थी। अगस्त में टमाटर की कीमत 102 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर सितंबर 2023 में 39 रुपये तक हो गई थी।

इनसाइड

घर खर्च के साथ आप भी कर सकती हैं अच्छी खासी बचत, फॉलो करें ये आसान टिप्स

आज के समय कमाने के साथ-साथ सेविंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम सही समय पर पैसे सेव नहीं करते हैं तो हमें भविष्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज हम कामकाजी महिला के साथ घरेलू महिलाओं को भी बताएंगे कि वो किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर सकती है।

नई दिल्ली। हर महिला कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करें। कई महिला पैसे सेव करने की कोशिश तो करती है पर उनसे पैसे सेव नहीं हो पाते हैं। अगर आप भी पैसे सेव करना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताते जिसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर पाएंगे। हमारे पास जब एक लक्ष्य होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर पाते हैं। ऐसे में आप भी एक फाइनेंशियल गोल बना सकते हैं। यह गोल आपके रिटायरमेंट के बाद की इनकम का हो सकता है या फिर कहीं घूमने को लेकर भी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि आपको लद्दाख जाना है तो आप उसके लिए अभी से पैसे सेव कर सकते हैं। आपको हर महीने का एक बजट बनाना चाहिए। जब देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें बजट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी तरह घर के खर्चों को पूरा करने और पैसे की बचत करने के लिए भी बजट की जरूरत पड़ती है।

NPCI ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया UPI का ब्रांड एम्बेसडर, वीडियो शेयर कर दिया खास संदेश

यूपीआई के साथ तेजी से प्रतिदिन करोड़ो ग्राहक पेमेंट करते हैं जिसके चलते अब यूपीआई से जुड़े स्कैम भी सामने आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज एनपीसीआई ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया गया है। यूपीआई ने देश में कैशलेस लेनदेन में सबसे बड़ा योगदान दिया है।

नईदिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के सेफटी एम्बेसडर बन गए हैं। देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा योगदान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने दिया है।

इस वजह से बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर

डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों पर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पंकज त्रिपाठी को अपने 'UPI Safety Ambassador' के रूप में नियुक्त किया है।

एनपीसीआई ने बताया कि यह कदम डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों की सुरक्षा के संबंध में चल रही चर्चाओं के मद्देनजर उठाया गया है।

UPI से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान

रिसीवर (Receiver) के नाम को वेरिफाइ किए बगैर पेमेंट ना करें।

यूपीआई पिन का इस्तेमाल तभी करें जब आपको कहीं पेमेंट करना है। पेमेंट प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ती।

QR कोड को सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन करें पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं।

अपने एटीएम पिन की तरह यूपीआई पिन को भी किसी से ना करें साझा।

केवल भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें, पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं।

आप यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े किसी भी सवाल के लिए एनपीसीआई के कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं।

सितंबर में कोर सेक्टर ने दर्ज की 8.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने पेश किए आंकड़े

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सितंबर में कच्चे तेल को छोड़ अन्य सभी के उत्पादन में सकारात्मक बढ़ोतरी रही जबकि कच्चे तेल के उत्पादन में पिछले साल सितंबर के मुकाबले 0.4 प्रतिशत की गिरावट रही। सितंबर में सबसे अधिक कोयले के उत्पादन में 16.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। आइए सभी आंकड़ों के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। इस साल सितंबर माह में कोर सेक्टर के उत्पादन में पिछले साल सितंबर के मुकाबले 8.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोर सेक्टर की यह बढ़ोतरी दर पिछले चार महीनों में सबसे कम है। आइए, सभी आंकड़ों के बारे में जान लेते हैं।

कोर सेक्टर में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी

इस साल अगस्त में कोर सेक्टर में पिछले साल अगस्त की तुलना में 12.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी तो इस साल के जून व जुलाई में कोर सेक्टर में क्रमशः 8.4 व 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। कोर सेक्टर में कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, स्टील, सीमेंट व बिजली जैसे आठ प्रमुख क्षेत्र शामिल है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने पेश किए आंकड़े

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सितंबर में कच्चे तेल को छोड़ अन्य सभी के उत्पादन में सकारात्मक बढ़ोतरी रही जबकि कच्चे तेल के उत्पादन में पिछले साल सितंबर के मुकाबले 0.4 प्रतिशत की गिरावट रही। सितंबर में सबसे अधिक कोयले के उत्पादन में 16.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

बिजली के उत्पादन में पिछले साल सितंबर के मुकाबले 9.3 प्रतिशत, स्टील में 9.6 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस में 6.5 प्रतिशत, रिफाइनरी उत्पाद में 5.5 प्रतिशत, सीमेंट में 4.7 प्रतिशत तो खाद के उत्पादन में 4.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

क्या कहते हैं आंकड़े?

आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ कोयले के उत्पादन में पिछले तीन महीनों से लगातार दहाई अंक में बढ़ोतरी हो रही है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में कोर सेक्टर में पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि की तुलना में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

HPCL के शेयरों ने लगाई लंबी छलांग, तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों ने जमकर खरीदे कंपनी के स्टॉक

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने सोमवार को अपने तिमाही नतीजों का एलान किया था। इस एलान में कंपनी ने बताया था कि सितंबर तिमाही में कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई है। जुलाई से सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5827 करोड़ रुपये रहा।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी में से एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) है। कंपनी ने सोमवार को सितंबर तिमाही के नतीजों का एलान किया है। इस नतीजें में कंपनी ने बताया कि उनका नेट प्रॉफिट इस तिमाही 5,827 करोड़ रुपये रहा। बीते तिमाही कंपनी घाटे में कारोबार कर रही थी जो इस तिमाही गोटे के दौर से निकलकर मुनाफे में बदल गई है।

तिमाही नतीजों के एलान के बाद कंपनी के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज कंपनी के शेयर सुबह 263.75 रुपये प्रति शेयर पर खुले थे। इसके बाद लगभग 10 बजे कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली। अभी भी कंपनी के स्टॉक में उतार-चढ़ाव जारी है। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर14.80 अंक की बढ़त के साथ 276.90 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रही है।

HPCL के तिमाही नतीजे

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बताया कि मार्केटिंग मार्जिन में बढ़ोतरी के बाद इनकम में सुधार ने सितंबर तिमाही में कंपनी को मुनाफे के दौर में वापस ले आया है। के बाद सितंबर तिमाही में मुनाफे में वापसी हुई। जुलाई-सितंबर 2023-24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,826.96 करोड़ रुपये दर्ज हुआ। वहीं, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि एक साल पहले की अवधि में कंपनी को 2,475.69 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

मार्केटिंग मार्जिन में बढ़ोतरी ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन पर रोक से पिछले साल दरें ऊंची होने पर हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में डाउनस्ट्रीम तेल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कारोबार से टैक्स के बाद की कमाई 6,984.60 करोड़ रुपये रही। एक साल पहले की समान अवधि में 2,462.57 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। पिछले साल यानी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने कीमतें कम कर दीं। यह उपभोक्ताओं को मूल्य अस्थिरता से बचाने के उद्देश्य से था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में घाटा हुआ। एचपीसीएल को अप्रैल-सितंबर 2022 में 15,118.41 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। हालांकि, इस साल उसने अप्रैल-सितंबर में 16,389.55 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कमाई की। इस साल जुलाई-सितंबर में कंपनी का राजस्व पिछले साल के 1.13 लाख करोड़ रुपये से गिरकर 1.02 लाख करोड़ रुपये हो गया।

विधानसभा चुनाव 2023: भाजपा को एक बार फिर मोदी के चेहरे पर भरोसा, कांग्रेस को अपने दमदार छत्रपों का सहारा

प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके और मध्यप्रदेश में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में जुटे सूत्र का कहना है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में शिवराज की छवि कहीं भी कमलनाथ से बहुत कमतर नहीं है। शिवराज के मुकाबले में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत अन्य काफी पीछे हैं...

नईदिल्ली। भाजपा ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और विकास के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। जबकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्यप्रदेश में छत्रप कमलनाथ और राजस्थान में अशोक गहलोत की सदारत में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव कहते हैं कि भाजपा की बारात बिना दूल्हे की है। अब देखिए जनता किस पर भरोसा करती है। कांग्रेस के नेता महेन्द्र जोशी कहते हैं कि इसमें कुछ कहने के लिए नहीं बचा। सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। जबकि भाजपा के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल के मुताबिक तीनों राज्यों में जनता भाजपा के साथ है। दोनों राज्यों में कांग्रेस की हार होगी और मध्यप्रदेश में भाजपा वापसी करेगी।

भाजपा के ही शिवराज सरकार में प्रभावी भूमिका में रहे सूत्र का कहना है कि राज्य में चुनाव मुख्यमंत्री जी को महत्व देने के बाद ही पटरी पर लौटा है। वह कहते हैं कि राजस्थान में भी देख लीजिए और छत्तीसगढ़ में भी। वसुंधरा राजे और रमन सिंह भले ही पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा न हों, लेकिन चुनाव प्रचार उनके चेहरे के इर्द-गिर्द केन्द्रित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल में सक्रिय रहे और कर्नाटक, हिमाचल के चुनाव प्रचार में बड़ी भूमिका निभाने वाले एक युवा नेता कहते हैं कि अभी भी सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे काफी ट्रेंड करते हैं। इनके मुकाबले में दोनों राज्यों में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन जनता के बीच में यह खबर भी आम है कि दोनों ही चेहरों की मुख्यमंत्री पद से छुट्टी होने वाली है। सूत्र का कहना है कि यह संदेश कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। इसका हमें फायदा होगा और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पार्टी वापसी करेगी। जबकि मध्यप्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।

अशोक, कमल, भूपेश खुद को अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में मान रहे हैं

कांग्रेस के नेता का कहना है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश में पार्टी के तीनों छत्रप मुख्यमंत्री की रेस में बने रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वह कांग्रेस का प्रमुख चेहरा हैं। जबकि भाजपा में उसके तीनों राज्यों के तीनों सबसे अधिक चर्चित चेहरे अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके और मध्यप्रदेश में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में जुटे सूत्र का कहना है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में शिवराज की छवि कहीं भी कमलनाथ से बहुत कमतर नहीं है। शिवराज के मुकाबले में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत अन्य काफी पीछे हैं। वह कहते हैं कि शिवराज की कई योजनाएं जनता के बीच में हैं। उनका सरल स्वभाव और संवाद भी लोगों में पसंद किया जाता है। सूत्र का कहना है कि 2018 में भाजपा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से पिछड़ गई थी। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद भाजपा ने शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही सरकार बनाई। दरअसल उस समय भी भाजपा के पास शिवराज का विकल्प नहीं था। संभव है कि इसका कुछ भाजपा को नुकसान हो। विंध्य क्षेत्र में घूम रहे वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्र मौर्य तो कहते हैं कि इधर हवा भाजपा के साथ जरा कम दिखाई दे रही है।

वसुंधरा, शिवराज रमन क्यों हुए किनारे?

भाजपा के एक प्रवक्ता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि 2018 में चुनाव से पहले वाला नारा (वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं) याद है न? वह कहते हैं कि इस बार भाजपा ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कई हिस्सों में रखकर चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है। हर हिस्से में वहां के बड़े चेहरे को मुख्य भूमिका दी गई है। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। यह काम चुनाव के बाद वहां के चुने हुए विधायक करेंगे। सूत्र का कहना है कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहां नेता थोपा नहीं जाता। भाजपा राज्य में विकास मुद्दे और अपने कामकाज के बल पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है।

आदित्य-एल1 ने कैप्चर की सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई-एनर्जी एक्स-रे झलक, इसरो ने दिया अपडेट

इसरो ने मंगलवार को अपने अपडेट में बताया कि आदित्य-एल1 पर लगे स्पेक्ट्रोमीटर ने लगभग 29 अक्टूबर, 2023 से अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान सोलर फ्लेयर्स के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है।

नईदिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का पहला सौर मिशन आदित्य एल-1 अपनी यात्रा पर है। इस बीच, अंतरिक्ष एजेंसी ने जानकारी दी है कि आदित्य-एल 1 अंतरिक्ष यान से जुड़े एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, एचईएल 1 ओएस ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई-एनर्जी एक्स-रे झलक कैप्चर की है। इसरो ने मंगलवार को अपने अपडेट में बताया कि आदित्य-एल1 पर लगे स्पेक्ट्रोमीटर ने लगभग 29 अक्टूबर, 2023 से अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान सोलर फ्लेयर्स के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। सौर वातावरण का अचानक चमकना ही सोलर फ्लेयर है। फ्लेयर्स विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम - रेडियो, ऑप्टिकल, यूवी, सॉफ्ट एक्स-रे, हार्ड एक्स-रे और गामा-रे में सभी तरंग दैर्ध्य (वेवलेंथ) में बढ़े हुए उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं। एचईएल 1 ओएस एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर वर्तमान में थ्रेसहोल्ड और केलिब्रेशन ऑपरेशंस के सुधार के दौर से गुजर रहा है। यह तब से कठिन एक्स-रे गतिविधियों के लिए सूर्य की निगरानी कर रहा है। इसरो ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर लिखा, यह उपकरण सूर्य की हाई एनर्जी एक्स-रे गतिविधि की निगरानी करने के लिए तैयार है, जिसमें तेज समय और हाई-रिजॉल्यूशन स्पेक्ट्रा है। एचईएल 1 ओएस डाटा शोधकर्ताओं को सोलर फ्लेयर्स के आवेगपूर्ण चरणों के दौरान रिली हुई विस्फोटक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है।

'जजों की नियुक्ति में पिक एंड चूज वाला रवैया परेशान करने वाला', सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पीठ को उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहां उसे या कॉलेजियम को कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो सुखद न हो।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विभिन्न हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार के द्रष्टिकोण को लेकर नाराजगी जाहिर की। पीठ ने कहा कि यह 'परेशान करने वाली बात है कि केंद्र उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए उन न्यायाधीशों को चुन-चुनकर अलग कर रहा है जिनके नामों की सिफारिश कॉलेजियम ने की थी।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पीठ को उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहां उसे या कॉलेजियम को कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो सुखद न हो।

अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें से एक में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी का आरोप लगाया गया था। इस दौरान न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण के लिए अनुशंसित नामों के लंबित रहने पर भी चिंता व्यक्त की।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि कई चीजों को फास्ट ट्रैक पर रखा गया है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि अभी तक पांच नाम हैं जो लंबित हैं जिन्हें दूसरी बार भेजा गया है। इसके अलावा 14 नाम और लंबित हैं। इन 14 नामों में परेशानी भरा पहलू यह है कि आपने नंबर 3,4,5 को नियुक्त किया है लेकिन नंबर 1 व 2 को नियुक्त नहीं किया गया है। ऐसे में वे वरिष्ठता खो देते हैं, यह स्वीकार्य नहीं है। मैं कभी भी किसी को न्यायाधीश पद स्वीकार करने का सुझाव नहीं दे पाऊंगा जिसके पास वकालत की अच्छी प्रैक्टिस है, वह जज बनने में दिलचस्पी क्यों लेना चाहेगा।

इस पर अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने कहा कि कुछ नामों पर तेजी से विचार किया गया है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा सवाल यह है कि मैं बार में अच्छी प्रैक्टिस करने वाले एक युवा सक्षम वकील को बेंच पर एक पद स्वीकार करके बलिदान देने के लिए कैसे मनाऊं।

वहीं, स्थानांतरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक न्यायाधीश को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में काम करना चाहिए या नहीं, यह न्यायपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वहीं, एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अटॉर्नी जनरलद्वारा दिए गए कई आश्वासनों के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने सरकार को इस मामले में काफी समय दिया है। ऐसे उदाहरण हैं जहां कई साल पहले दोहराव किया गया था। यह कब तक चल सकता है। यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। अब समय आ गया है कि सख्ती की जाए अन्यथा सरकार को यह आभास हो रहा है कि वह कुछ भी करके बच सकती है। वहीं, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि बार-बार अदालत से आग्रह करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और यदि कोई समयसीमा निर्धारित की जाती है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। इस मामले में अब 20 नवंबर को सुनवाई होगी।

राजधानी भुवनेश्वर शर्मसार: 5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या

मनोरंजन सासमल, ओड़िशा

भुबनेस्वरः राजधानी भुवनेश्वर में एक शर्मनाक घटना घटी है. 5 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई. बच्चे की बेरहमी से धड़ काटकर हत्या की गई थी. यह अमानवीय घटना भुवनेश्वर एयरफील्ड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सुंदरपाड़ा केला बस्ती में हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद जब आरोपी मौके से लौटे तो स्पेशल स्क्वाड और एयरफील्ड पुलिस स्टेशन को चैनविन के लिए रवाना किया गया. उसके लौटने से पड़ोस के युवक घनिया पर शक गहरा गया है।

मेरा ओडिशा नवीन ओडिशा एक बोर्ड या कॉर्पोरेशन - सांसद प्रताप सारंगी

मनोरंजन सासमल, ओड़िशा

भुबनेस्वरः हमारा ओडिशा नवीन ओडिशा एक फर्जी योजना है। इसका मकसद लोगों को धोखा देना है. ग्राम सभा, पल्ली सभा के बिना निर्णय लिये जाते हैं। ओडिशा नवीन क्या ओडिशा एक बोर्ड या निगम है? इसकी अध्यक्षता की जायेगी. इसका उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना है. आज बीजेपी सांसद प्रताप षाड़ंगी ने एक बार फिर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'आम ओडिशा नवीन ओडिशा' की आलोचना की है. प्रताप की शिकायत के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि बदले हुए ओडिशा में क्या हो रहा है? सत्ता पर कब्जा करने की साजिश हो रही है. सत्तारूढ़ बीजे विधायक प्रशांत मुदुली ने दोनों विपक्षी दलों के आरोपों का कड़ा जवाब दिया. हमारी ओडिशा नवीन ओडिशा योजना एक बार फिर विवादों में है।आज बीजेपी सांसद प्रताप षाड़ंगी ने कहा, 'आम ओडिशा नवीन ओडिशा एक फर्जी योजना है. लोगों को धोखा देने की योजना. ग्राम सभा, ग्राम सभा, कुछ नये निर्णय लिये जा रहे हैं। 5 चेयरमैन पैसा इकट्ठा कर रहे हैं. सीई किसके अध्यक्ष हैं? 5 या हमारा ओडिशा नवीन ओडिशा कोई बोर्ड या निगम है जिसका एक चेयरमैन होगा? मूलतः यह लोगों को मूर्ख बनाने की योजना है। ओडिशा में अनेक महापुरुष हुए। उनके नाम पर योजना क्यों नहीं बनाई? ओडिशा नवीन बाबू की पैतृक संपत्ति नहीं है. पिछले अक्टूबर में लॉन्च हुए आम ओडिशा नवीन ओडिशा पर सरकार करीब 4 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. योजना के माध्यम से राज्य के मठों, मंदिरों, विभिन्न समुदायों के धार्मिक स्थलों, ग्रामीण पूजा स्थलों और विरासत और पर्यटक आकर्षणों का विकास किया जा रहा है। जिसके लिए प्रत्येक पंचायत को 50 लाख का वित्तीय अनुदान दिया जाता है। योजना पर शुरू से ही विवाद रहा है. ऐसे में एक बार फिर इस योजना को लेकर आरोप लग रहे हैं. यह योजना सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल को राजनीतिक लाभ देती है।

उपकुलपति के खाली पद पर रार, पसमांदा महाज के अध्यक्ष ने कहा- नियुक्ति की प्रक्रिया गलत और असंवैधानिक

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खाली पड़े पद को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कोर्ट मेंबर्स ने तीन सदस्यों में से एक नाम केंद्र की मुहर के लिए भेज दिया है। वहीं ऑल इंडिया पसमांदा महाज के अध्यक्ष शारिक अदीब ने इस प्रक्रिया को गलत, अवैध, असंवैधानिक बताया। साथ ही साथ पूरे मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप औ संशोधन की मांग की है।

बता दें छह नवंबर को एएमयू कोर्ट ने प्रोफेसर और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एमयू रब्बानी, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा एवं महिला प्रत्याशी प्रोफेसर नईमा खातून के नामों का पैनल तैयार किया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास एएमयू वीसी के चयन के लिए भेजा जाना है। इससे पहले दो नाम और चयन किए थे।

शारिक अदीब ने आरोप लगाया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक ऐसा अड्डा बन गया है, जो देश में ऊंच, नीच और जातिवाद को खुलेआम बढ़ावा देकर पसमांदा समाज का बेशर्मी से गला घोंट रहा है। अदीब का तर्क है कि हिन्दुस्तान में लगभग 80 से 85 फीसदी पसमांदा समाज है लेकिन 15 फीसदी तथाकथित उच्च वर्ग के मुस्लिम लोगों ने विश्वविद्यालय पर कब्जा कर रखा है।

पसमांदा समाज के अध्यक्ष अदीब ने आरोप लगाया कि लंबे समय से एएमयू में ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे ऊंची जाति का ही वीसी चुना जाता है। अदीब का आरोप है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल एवं एएमयू कोर्ट के जरिए एएमयू का वीसी चयन करना अप्रासंगिक और अवैध है।

कला संवाद 2023 का आयोजन, विभिन्न स्कूलों के लगभग 280 छात्र-छात्राओं ने लिया भाग

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विभिन्न 16 स्कूलों के लगभग 280 छात्र-छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।कार्यक्रम की शुरुआत में स्टूडेंट सोसाइटी की मेंबर सचिव डा श्वेता बोहरा ने कला मंथन की रूपरेखा को बताया।

सोफिया स्कूल ने मारी विजेता ट्रॉफी पर बजी

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। संगम विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स तथा लिटरेरी सोसाइटी द्वारा कला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत अमृत मंथन तथा कलाकृति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संगम विश्वविद्यालय के स्टूडेंट अफेयर डायरेक्टर प्रो विनेश अग्रवाल की ने बताया कि कला संवाद में अमृत मंथन के अंतर्गत सदन की सम्मति में सोशल मीडिया आज की पीढ़ी के लिए एक उपयोगी अस्त्र है, विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता तथा ऑन स्पॉट विभिन्न विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।कलाकृति कार्यक्रम में हैंडमेड, स्केच, ज्वैलरी प्रदर्शनी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, फेस पेंटिंग, ब्रशलेस पेंटिंग, लोगो मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विभिन्न 16 स्कूलों के लगभग 280 छात्र-छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।कार्यक्रम की शुरुआत में स्टूडेंट सोसाइटी की मेंबर सचिव डा श्वेता बोहरा ने कला मंथन की रूपरेखा को बताया।

प्रो विनेश अग्रवाल ने बाहर से आई सभी प्रतिभागी टीम का परिचय कराया तथा सभी को जीतने की बधाई दी।कुलसचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों के बारे में छात्र-छात्राओं को बताया। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मानस रंजन ने सभी आगंतुक प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा विश्वविद्यालय के सभी डीन तथा कोर्स से अवगत कराया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एनएचएआई की प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रतिमा गुप्ता ने विश्वविद्यालय द्वारा इस अनूठी पहल तथा विभिन्न स्कूल के एक साथ संगम करने केलिए बधाई दी।विश्वविद्यालय में संचालित महिलाओं के उत्थान के लिए गठित तेजस्विनी सेल की रूप रेखा प्रो प्रीति मेहता द्वारा बताई गई।कुलपति प्रो करुणेश सक्सेना ने ऑनलाइन सभी को बधाई दी।

कला संवाद प्रतियोगिता के परिणाम में सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रथम स्थान में परिणाम के रूप में कलाकृति में पेंटिंग में प्रथम संपत प्रजापत राजेंद्र मार्ग स्कूल, हैंडमेड क्रिएटिव में हर्षिता, मनस्वी जैन सोफिया स्कूल, हैंडमैड ज्वेलरी में मीनाक्षी शर्मा कुम्भा विद्यानिकेतन स्कूल, लोगो डिजाइन में प्रियांशु सारस्वत सेंट एंसलम स्कूल, ब्रशलेस पेंटिंग में ज्योति यादव मयूर स्कूल, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में ताशु, मालविका शेखावत, नव्या नुवाल सोफिया स्कूल, फेस पेंटिंग में तानिया कालरा सोफिया स्कूल, वाद विवाद अंग्रेजी में निहारिका सिंह सोफिया स्कूल, वाद विवाद हिंदी में पूर्वी हरीचा सोफिया स्कूल, निबंध प्रतियोगिता अंग्रेजी में मणिकर्णिका सिंह संगम स्कूल, निबंध हिंदी में सांवरमल जाट महेश दीक्षा सदन प्रथम रहे।सभी कलाकृति के विजेताओं को प्रथम स्थान पर 2100 रुपए तथा द्वितीय स्थान पर 1100 रुपए का नगद पुरस्कार, सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी दी गई, अमृत मंथन कार्यक्रम के सभी विजेताओं में प्रथम को 5000, द्वितीय को 3000, तथा तृतीय स्थान को 2000 रुपए नकद, सर्टिफिकेट ट्रॉफी दी गई।कार्यक्रम के अंत में विश्वविद्यालय के मार्केटिंग हेड अमित जैन ने सभी छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय के कोर्स पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी।तेजस्विनी सेल द्वारा महिलाओं के कला कौशल विकास के लिए विभिन्न महिलाओं ने स्टॉल लगाई।प्रतियोगिता के सफल आयोजन के निर्णायक सदास्यो में रिक्कू मानस, रीना डाड, सीमा सांखला, योगेश दाधीच, कैलाश पालिया, चंद्रेश टेलर थे।कार्यक्रम के सफल संयोजन में डा श्वेता बोहरा, नेहा शब्बरवाल, करुणा लड्ढा, डॉ कीर्ति, डा अवधेश, पूनम चौहान, पल्लवी पुरोहित, डा रेखा, शालू अग्रवाल, अदिति नरेडिया, पवन अत्रे आदि का सहयोग रहा।कार्यक्रम में सभी स्कूल से पधारे फैकल्टी कॉर्डिनेटर तथा सभी प्रतिभागी को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट दिया गया।सोफिया स्कूल भीलवाड़ा को विजेता रनिंग ट्रॉफी दी गई।कार्यक्रम के अंत में नेहा शब्बरवाल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023